RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ...सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-03, अंक - 51 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 23 सितम्बर 2021 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है... उलट, सवाल यह है कि कितना भुलाया जा सकता है।

ओशो

जिले में नहीं थम रहा बॉयोडीजल के अवैध धंधे का खेल, सेटिंग के चलते नहीं होती कार्रवाई सार्वजनिक

DM/C
Demand, Money / Collection

डीमांड, मनी / कलेक्शन का है पूरा खेल...

वैध पेट्रोलियम डीलर से चार गुना तक ज्यादा कमाई करते अवैध धंधेबाज

अंतरवेलिया स्थित जयदीप बॉयो फ्यूल पंप पर प्रशासनिक अमले ने कार्रवाई तो की लेकिन उजाकर नहीं की।

छापरी स्थित अवैध बॉयोडीजल पंप पर अपने गुर्गों के साथ तैनात सोनू।

पिटोल में अब लगातार जारी है रात के अंधेरे में बॉयोडीजल का गौरख धंधा।

माही की गूंज टीम के साथ संजय भटेवरा की रिपोर्ट

जिले में इन दिनों बॉयोडीजल के नाम पर अवैध धंधेबाजों का जाल कुछ इस तरह बिछता जा रहा है कि वैध और सादे डीजल का धंधा करने वालों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैध और अधिकृत पेट्रोल पंपों की कमाई से बॉयोडीजल के इन अवैध धंधेबाजों का काला मुनाफा इतना ज्यादा है कि, इसका मुकाबला ही नही किया जा साकता। बॉयोडीजल व सादे डीजल की कमाई में करीब चार गुना से अधिक का अंतर है। इन माफियाओं ने अधिकृत पेट्रोल-डीजल विक्रेताओं की नींद हराम कर रखी है।

इस अवैध बॉयोडीजल के काले धंधे की अकूत कमाई से प्रशासनिक अमला भी बहती गंगा में हाथ धोता नजर आ रहा है। जबकि वैध पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अवैध बॉयोडीजल की इस अकूत कमाई में ऊपर से लेकर नीचे तक तंत्र में सभी का अपना-अपना हिस्सा या कमीशन तय है। (डीएम/सी) डीमांड मनी/कलेक्शन... का यह खेल आला रूतबे के अधिकारी अपने अधीनस्तों के जरिए करवाते, वहीं अधिनस्त भी बहती गंगा से अपना लौटा तो भर ही लेते। इन अवैध धंधेबाजों की तूती इतनी आवाज करती कि, वे जानकारी देने के बजाय यह बताते नहीं थकते कि कहां और किस अधिकारी को कितना-कितना खिलाया है और अवैध धंधा करने में कौन सा अधिकारी उनका संरक्षक है। जिला स्तर से लेकर तहसील व थाने के अधिकारियों के नाम इनके मुंह पर ऐसे रटे है कि वे इनका इस्तेमाल करते हुए जानकारी मांगने वालों को डराने - धमकाने से भी नहीं चूकते।

पिटोल से लेकर धार जिले के दत्तीगांव तक ये अवैध धंधेबाज सरकारी संरक्षण में अपना साम्राज्य जमाए बैठे है। इन में से किसी ने आदिवासियों की जमीन किराए पर ले रखी और उस पर बकायदा सिर्फ डीजल की मशीन लगाकर बॉयोडीजल के नाम पर अवैध डीजल बेचा जा रहा है। जबकि कई खुले आसमान के नीचे बॉयोडीजल के नाम पर अवैध और नकली ईंधन से भरे टेंकरों पर डायरेक्ट छोटी मशीन लगाकर वाहनों में ईंधन भरते। जब कहीं शिकायतों के बाद कार्रवाई के नाम पर कोई हलचल होती तो यह अवैध धंधेबाज अपने टैंकर से नेशनल हाइवे पर गस्त करते हुए अपना काला माल खपा देते है।

यह है वैध-अवैध कमाई में अंतर

अंचल के वैध और अधिकृत पेट्रोल पंपों पर इन दिनों सादे डीजल का मुल्य लगभग 98 रुपए प्रति लीटर के आसपास चल रहा है। इसके मुल्य में प्रतिदिन उतार-चढ़ाव बना रहता है। पेट्रालियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक मध्यप्रदेश में पेट्रोल पर 33 प्रतिशत वेट प्लस 4.5 प्रति लीटर का निश्चित वेट 01 प्रतिशत सेस लगता है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 30 प्रतिशत और डीजल पर 22 प्रतिशत टैक्स वसूला जाता है। जो डीजल पर करीब 21.68 रुपए प्रति लीटर है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पेट्रोल पर 55 प्रतिशत और डीजल पर 50 प्रतिशत टैक्स वसूलती है। जबकि डीलर का कमीशन पेट्रोल पर 3.55 रुपए और डीजल पर 2.37 रुपए प्रति लीटर है।

दूसरी और प्रदेश सरकार की बायोडीजल को लेकर अब तक कोई निती स्पष्ट नहीं है। लेकिन खोज बीन करने पर यह पता लगा कि, वर्तमान में बॉयोडीजल 72 रुपए प्रति लीटर के मुल्य पर बिक रहा है। इसका मुल्य निर्धारण 6 माह में निर्धारित किया जाता है और यह जीएसटी की 18 प्रतिशत दर में शामिल है। इसके अलावा इस पर कोई टैक्स नहीं है। वर्तमान स्थिति में साधारण डीजल के मुकाबले बॉयोडीजल 26 रूपए के लगभग सरकारी दर के अनुसार सस्ता है। सुत्रों के अनुसार बॉयोडीजल के रेट में करीब 10 रुपए तक डीलर का कमीशन होता है। मगर अवैध धंधेबाज बायोडीजल लगभग 65 से 67 रुपए प्रति लीटर में ही उपलब्ध करवा देते है। अब सवाल यहां यह भी खड़ा होता है कि, क्या वाकई देश में बॉयोडीजल का इतना उत्पादन हो रहा है...? जबकि पूरे देश में चुनिंदा प्लांट ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे है या फिर अवैध धंधेबाज बॉयोडीजल के नाम पर एक नकली और अवैध ईंधन बनाकर बैच रहे है...?

अगर मान लें कि एक वैध अधिकृत पेट्रोल-डीजल विक्रेता अगर दिन में 10 हजार लीटर डीजल बैचता है तो डीलर कमीशन के अनुसार 2.37 रुपए के मान से उसका कमीशन 23 हजार 700 रुपए होता है। इसके उलट बॉयोडीजल के नाम पर अवैध व नकली ईंधन बैचने वाले 65 से 67 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बैचने के बाद भी 5 से 7 रुपए प्रति लीटर की अवैध कमाई कर जाते है। इस तरह अगर वे दिन में 10 हजार लीटर अपना अवैध और नकली ईंधन बैचते है तो उसकी अवैध कमाई सादे डीजल के अधिकृत विक्रेता से दो गुना से भी अधिक हो जाती है। जो लगभग 50 हजार प्रतिदिन होती है। अगर यह नकली व अवैध ईंधन के काले धंधेबाज अपने नकली ईंधन को बायोडीजल के अधिकृत दर से बैचते है तो इनकी अकूत कमाई एक लाख से भी अधिक प्रतिदिन तक पहुंच जाती है।

लाखों की अवैध और अकूत कमाई से होता सेटलमेंट

जैसा कि हम अपने पिछले अंक में बता ही चुके है कि, पिटोल से लेकर धार जिले के दत्तीगांव तक इन अवैध और नकली बायोडीजल के विक्रेताओं का साम्राज्य फैला हुआ है। धार जिले की सीमा को छोड़ भी दें तो पिटोल से माछलिया के बीच आधा दर्जन से अधिक जगहों पर इस तरह के अवैध बॉयोडीजल के धंधे चल रहे है। इस धंधे में लिप्त हर अवैध धंधेबाज की इनकम भी एक-दूसरे से उन्नसी-बीसी होगी। सभी अवैध बायोडीजल के धंधेबाज अपनी अकूत काली कमाई से सेटिंग करते और सेटलमेंट भी। अवैध धंधेबाजों के लिए अपनी अंकूत कमाई से अधिकारियों का पेट भरना भी आसान ही होता।

भैया अपनी सेटिंग हो गई, थोड़े दिन बाद अपन ही बेचेंगे ....

बॉयोडीजल के नाम पर नकली ईंधन बेचने वाले सबसे बड़े गुजरात के माफियाओं का नाम सामने आ रहे है। स्थानीय रसूखदारों ने हाईवें पर स्थित हॉटलों एवं ढाबा संचालकों की मदद से गुजरातियों ने अच्छा खासा व्यापार जमा लिया है। और तो और स्थानीय माफिया भी पूरे जिले में प्रशासन के नाम का गाना गाते फिर रहे है कि, बस अपनी सेटिंग हो गई है, अब अपन पंप चलाएंगे। अवैध ईंधन के बारे में अंदरखानों की माने तो बॉयोडीजल के नाम पर टेंकरों में सायलो एवं एलडीओ नामक केमिकल गुजरात से लाया जा रहा है। बताते है इन केमिकलों में एक अन्य केमिकल की मिलावट करने से हुबहु डीजल जैसा दिखाई देता है। हाई स्पीड डीजल से काफी सस्ता होने से इसकी बिक्री जोरों पर हो रही है, तो इस नकली ईंधन से संबंधित किसी प्रकार के कोई कागजात टेंकर चालकों के पास नहीं होते। कुल मिलाकर अवैध धंधेबाज नकली ईंधन ही नहीं अपितु टेक्स चोरी का भी बड़ा खेल खेल रहे है। ईंधन विक्रय से जितना लाभ इन धंधेबाजों को होता लगभग उतना ही टेक्स

चोरी कर बचा लेते। डीजल माफियाओं के दोनों हाथों में लड्डू लिए प्रशासनिक व राजनेतिक गठजोड़ के साथ बेखौफ धंधा कर रहे है।

टेंकरों से सीधे बेच रहे डीजल

अवैध बॉयोडीजल और प्रशासन के मध्य तू डाल-डाल और मैं पात-पात वाली स्थिति इन दिनों बनी हुई। हालांकि हमारा मत प्रशासन के दुध के धुले होने का बिलकुल नहीं है, किंतु फिर भी शिकायतें होने पर प्रशासन कार्रवाई के लिए न चाहते हुए भी निकल पड़ता है। झाबुआ अनुभाग के बड़े अधिकारी इन दिनों खूब कार्रवाई कर रहे और मलाई चाटने को लेकर इनके उपर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगे हुए है। हालांकि डीजल माफिया, कलेक्टर तक को खरीदने की बात बाजारों में कहते फिर रहे है, तो कईयों ने राजनैतिक संबंधों का सहारा लेना भी प्रारंभ कर दिया है। बताते है प्रशासन एक पंप सील करता तो दो अन्य जगहों पर पंप लगाने की जुगत प्रारंभ हो जाती है। कोई दस दिन पूर्व पिटोल में जिस सागर हॉटल के समीप अवैध बॉयोडीजल पंप प्रशासनिक अमले ने सील किया था उसी स्थान पर सीधे टेंकर से बड़े वाहनों में अवैध ईंधन रोज रात्रि में भरा जा रहा था। और तो और यह सब कानवाई लगाने वाले पिटोल पुलिस सामने ही होता रहा, किंतु इसे माफियों की दहशत ही कहेंगे कि कार्रवाई के बाद पुनः अवैध डीजल बिक्री पुलिस के सामने निर्बाध जारी है। यही स्थिति देवझिरी, कालीदेवी की है। कालीदेवी पंप सील करने के बावजूद रात्रि में ईंधन बिक रहा है तो पिटोल की तर्ज पर देवझिरी वालों ने भी चलता फिरता पंप संचालित कर रखा है।

धमकाने के लिए पाल रखे गुर्गे

प्रशासनिक कार्रवाई से बेखौफ होकर धंधा करने वाले डीजल माफियों ने चलता फिरता न सिर्फ पंप खोल लिया, अपितु धमकाने व चमकाने की पूरी व्यवस्था भी कर रखी है। बताते है मीडियाकर्मी अथवा निचले प्रशासनिक कर्मचारी जैसे ही पंप पर पहुंचते सर्वप्रथम वहां उपस्थित ग्रामीणों का सामना करना पड़ता है। पिटोल वाले माफिया ने तो बकायाता बंदूकधारी तैनात कर रखा है, तो रात्रि में स्वयं भी अपने अवैध कृत्यों की निगरानी रखता है। कोई पंप की तरफ जाए तो चाबी भरे गुर्गे धमकाना प्रारंभ कर देते। बंदूकधारी भी सामने आ जाता और आने वाले से ही सवाल-जवाब करने लगते है। कुल मिलकार अवैध कारनामे करने वाले डीजल माफिया अवैध कार्य भी दादागिरी से कर रहे है।

अंतरवेलिया में हुई कार्रवाई अचंभित करने वाली

गत सप्ताह अंतरवेलिया ग्राम में जिस बॉयोडीजल पंप को प्रशासन ने सील किया उसके बारे में बताते है, वैध दस्तावेज सबसे ज्यादा उसके पास ही है। कहने वाले तो यह भी कहते है कि, भेंट-पूजा सबसे ज्यादा अंतरवेलिया वाले द्वारा ही की जाती है। बावजूद इसके अंतरवेलिया में हुई कार्रवाई माफियाओं की राजनैतिक रसूख की ओर ईशारा करती है। जानकार तो यह भी बताते है कि, बॉयोडीजल पंप खोलने हेतु बनने वाले कागजों में कुछ दस्तावेज ऐसे भी है जिस पर सरकारों ने ही प्रतिबंध लगा रखा है। इसीलिए बायोडीजल पंप अपने आपमें अवैध है और अन्य माफियाओं की तरह जिला उनकी पनाहगार बनने की ओर अग्रसर है। ज्ञातव्य है कि, अवैध बॉयोडीजल को लेकर गुजरात सरकार सख्त है तो एमपी में भी महानगरों के आसपास के सभी बॉयोडीजल पंप को वहां का प्रशासन सील कर चुका है।

जैसा कि गूंज 'बेबाकी के साथ सच' को साकार करते हुए 'माही की गूंज' के पिछले अंक में 'न नियम न कायदा, बस सेटिंग और फायदा ही फायदा' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस काले धंधे व इससे जुड़े तमाम बागड़ बिल्लों को उजागर करने की शुरूआत कर दी है।

गूंज टीम की अवैध बॉयोडीजल विक्रेताओं पर अगले अंकों में भी पैनी नजर बनी रहेगी, क्या है गुजरात वाले चचा की कहानी, क्या कहते है नियम, प्रशासन की संदेहास्पद भूमिका आदि विषयों पर अगले अंक में होगा खुलासा...

मोबाईल नंबर दे दो निराश नहीं होने दूंगा

ऐसे ही छापरी स्थित एक अवैध बॉयोडीजल पंप मालिक व इस अवैध और अकूत धंधे में लिप्त सोनू भी है। अपने आपको आदिवासी बताने वाले सोनू ने अवैध बॉयोडीजल के नाम पर संचालित नकली ईंधन पंप पर ही अपने चार-छः गुर्गे पाल रखे है। जो भी उसके अवैध धंधे पर नजर डालता उसके गुर्गे जरा सी भी हलचल होने पर किसी को भी घेर लेते और धमकाते हुए सेठ से बात करने का दबाव बनाने लगते। जब गूंज टीम बॉयोडीजल के नाम पर हो रहे इस अवैध धंधे की रिपोर्टिंग के लिए वहां पहुंची और अपने कैमरे से फोटो लेना शुरू किए तो सोनू के पाले हुए गुर्गों ने दौड़ लगाते हुए आकर गूंज की टीम को घेर लिया और डराने धमकाने लगे। जब डराने धमकाने से बात नहीं बनी तो, सोनू के गुर्गों ने मोबाईल व कैमरा छीनने की कोशिश करते हुए फोटो डीलीट करने का दबाव बनाया। जब यहां भी दाल नहीं गली तो गुर्गों ने गूंज टीम को घेरते हुए आकर सेठ से बात करने को कहा। गुर्गों से घिरी गूंज टीम जब अवैध धंधेबाज से बात करने पहुंची तब भी सोनू के गुर्गों ने उसे घेरे रखा। जब गूंज टीम ने सोनू से बहस की और कहा कि, आपका यह डीजल पंप अवैध है, तो सोनू का कहना था कि, हम आदिवासी समाज के लोग है और अगर आप जैसे लोग हमें हमारे ही जिले में आगे नहीं बढने़ देंगे तो कैसे चलेगा। सोनू यह भी बताता है कि, हमारे अलावा भी तो बाहर से आकर यहां कई लोग इस तरह का अवैध धंधा कर रह है। उनसे भी पूछताछ कीजिए। इस बॉयोडीजल के अवैध धंधे में अधिकतर लोग गुजरात के गोधरा क्षेत्र के है, हम तो स्थानीय है। मगर वह बाहरियों की जानकारी देने से भी बचता रहा।

अवैध तो अवैध है चाहे स्थानिय हो या बाहर का

अवैध तो अवैध है, चाहे फिर वह स्थानीय लोग करे या बाहरी लोग...? इस सवाल के जवाब में सोनू कहता है कि, हमारा व्यवसाय अवैध नहीं है। इसके रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई जारी है। कुछ कागज और बनने के लिए दिए है, एनओसी भी जल्द ही मिल जाएगी। जब गूंज टीम ने पेट्रोल-डीजल पंप खोलने के अपने अनुभव साझा किए तो सोनू की हेकड़ी थोड़ी ढीली पड़ी और वह गूंज टीम से कहने लगा आप मुझसे क्या चाहते है। जो भी होगा देख लेंगे...! आपको निराश नहीं होने दूंगा...! मगर गूंज टीम ने उसे स्पष्ट कहा कि या तो यह प्रुफ करे कि, वह यह डीजल पंप वैध तरीके से चला रहा है या गूंज अपना काम करते हुए जिले में चल रहे इस अवैध कारोबार को उजागर करेगा। जब गूंज टीम ने सवाल किया कि आपके डीजल पंप पर रात के अंधेरे में किसी थाना अधीकारी का वाहन खड़ा था, उसके बावजूद भी आप अवैध डीजल की बिक्री कर रहे थे...? तब सोनू बताता है कि, वह किसी थाना अधिकारी का वाहन नहीं था वह तो तहसीलदार साहब का वाहन था। जब हमने सोनू से पूछा कि तहसीलदार का नाम क्या है...? तो सोनू अंजान व नादान बनकर इससे अनभिज्ञता जताते हुए कहता है कि मुझे तहसीलदार साहब का नाम नहीं पता। जब हमने यह जानने की कोशिश की कि उसकी कहां-कहां और किस-किस अधिकारी से सेटिंग है...? तो सोनू बात को टालते हुए गूंज टीम को मसखा लगाने लगा और फोन नंबर मांगते हुए कहने लगा कि जो भी होगा मैं आपसे फोन पर बात कर लूंगा। घबराए सोनू ने गूंज टीम पर घात लगाए बैठे अपने गुर्गों को हटाया और गूंज टीम से बाद में बात करने का कहकर रवाना कर दिया।

कल्याणपूरा कांग्रेस में सेंध लगाने की तैयारी में भाजपा, यहां भी कांग्रेस के नेता थाम सकते है भाजपा का दामन

'आ बैल मुझे मार' की स्थिति में कांग्रेस

यहां अगर सेंध लगी तो कांग्रेस को बैठने लायक जगह भी नहीं होगी नसीब

माही की गूंज, झाबुआ।

लगातार देखने मे आ रहा है कि, कांग्रेस-भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पार्टी बदलने में लगे हुए है। चुनाव से पहले दोनों दलों में हलचल तेज़ है, रायपुरिया क्षेत्र में कांग्रेस को हुए डेमेज की अभी भरपाई भी नही हुई थी कि, भाजपा की अयोध्या कहे जाने वाले कल्याणपूरा क्षेत्र से भी कांग्रेस के कई नेताओं की भाजपा में शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है।

कल्याणपुरा एक ऐसा क्षेत्र है, जहा भाजपा लगातार चुनाव में लीड करती आ रही है पर पिछले परिणाम देखे जाए, तो यहां पर भाजपा के विपरीत परिणाम देखने को मिले है ओर इस क्षेत्र से कांग्रेस बड़ी लीड लेने में कामयाब रही और भाजपा का मिथक भी तोड़ दिया कि यहा भाजपा का परम्परागत वोट बैंक है ।

संगठन में पूछ परख और नेताओं द्वारा ध्यान नहीं देने से कार्यकर्ता नाराज़

नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी बदलने के निजी कारण कुछ भी हो लेकिन पार्टी बदलने वाले नेता ज्यादातर एक ही तर्क देते है कि, वो अपने दल के नेता और उनके निर्णय से संतुष्ट नही है। कल्याणपुरा में पिछले वर्षों में कोंग्रेस ने बड़ी सेंध लगाते हुए भाजपा के सेंकडो लोगो को तोड़ा ओर कोंग्रेस में शामिल किया। यहां जब पूर्व मे मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा हुई तो एक साथ मे 100 लोगो को कोंग्रेस की सदस्यता दिलाई गई थी, यह सब वहां के नेताओ की मेहनत ही थी, जिन्होंने कोंग्रेस को मजबूत किया। नही तो पुराने नेता तो वही ÷भूरिया जी चुनाव आया और जेब भारी÷ कहावत चल रही थी। जब मतों की गणना होती तो 150 से 200 वोट के अंदर नगर में और आसपास के क्षेत्र मिलाकर यहाँ से भाजपा10 से 11 हजार करीब लीड लेती थी, पर जब से कमान यहां के युवाओं के हाथ मे आई है तब से ही कोंग्रेस नगर ही नही पूरे क्षेत्र मे मजबूत स्थिति मे है। पिछले कई महीनों से लगातार अपनी उपेछा का शिकार हो रहे स्थानीय नेता अब परेशान से हो गए है उन्हें न तो कोई बैठक में बुलाया जाता है, न कोई सूचना दी जाती है और न ही जिले के

संगठन के लोगो द्वारा उन्हें कभी पूछा भी नही जाता। ऐसे में अब यहां के नेता कोंग्रेस नेताओ द्वारा मान सम्मान नही देने के कारण अब लगातार भाजपा के सम्पर्क में आते जा रहे है और लगातार भाजपा की सदस्यता लेने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। अगर ऐसा होता है तो ये तय है कि, यहां पर कोंग्रेस नेताओ को बेठने की जगह भी नसीब नही होगी।

कोंग्रेस और उनके बड़े नेताओं को आत्ममंथन की जरूरत

कल्याणपूरा के भाजपा समर्थित सरपंच ने परवाह किए बिना सरकार में बैठी भाजपा को छोड़ कोंग्रेस की सदस्यता ली और कोंग्रेस के युवा नेताओ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता में बैठी भाजपा से यहाँ मुकाबला कर रहे है। ऐसे में यहां के कांग्रेस नेताओ के मन मे पार्टी बदलने के विचार बन रहे है, तो कांग्रेस और उनके बड़े नेताओं को आत्ममंथन की आवश्यक है, कि विपक्ष में होने के बाद भी कांग्रेस के बड़े नेता जमीनी कार्यकर्ताओ को नही पूछ रहे है, तो सत्ता में आने पर इनको कौंन पूछेगा। उक्त कमजोरी को भाजपा ने पकड़ कर नेताओ को सत्ता सुख के साथ-साथ संगठन से पद ऑफर कर अपनी और भाजपा में शामिल करने में कामयाब हो रहे है।

यूथ कोंग्रेस की जिला कार्यकारिणी में कल्याणपूरा क्षेत्र की हुई उपेक्षा

विगत दिनों पहले जिला यूथ कोंग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की उसमे पूरे जिले से सभी क्षेत्र के लोगो के नाम है। लेकिन कल्याणपूरा क्षेत्र को यूथ कांग्रेस ने अनदेखा किया, और यहाँ से एक भी नाम उस कार्यकारिणी में नही शामिल किया गया है। इतने बड़े क्षेत्र से एक भी योग्य युवा पदाधिकारी कोंग्रेस को नही मिला ये विचारणीय है। संगठन में लगातार अनदेखी से क्षुब्ध कई युवा नेताओ के पास भाजपा जैसा विकल्प मौजूद है , जिसकी और भाजपा के लगातार प्रयास जारी है, वही कांग्रेस खुद की नीति के कारण ÷आ बैल मुझे मार÷ की स्थिति में आकर खड़ी हो गई है।

जनभागीदारी समीति की बैठक में हुए अहम निर्णय

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में शहीद चन्द्रशेखर आजाद,शासकीय स्नातकोत्तर महाविघालय झाबुआ की जनभागीदारी समिति सामान्य परिषद की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में सांसद प्रतिनिधि अर्पित कटकानी, विधायक प्रतिनिधि विनय भाबोर, जिला कोषालय अधिकारी झाबुआ सदस्य वित्त समिति ममता चंगोड़, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग झाबुआ सदस्य प्रबंधन समिति रेशम गामड़, डॉ. जे.सी. सिन्हा प्राचार्य/सचिव एवं अध्यक्ष वित्त समिति, मनोज अरोडा सदस्य सामान्य परिषद, अशोक भावसार सदस्य सामान्य परिषद, हट्टू सिंह डामर सदस्य सामान्य परिषद, रेखा मोदी सदस्य सामान्य परिषद, डॉ. रविन्द्र सिंह सदस्य वित्त समिति, डॉ. संजू गांधी सदस्य वित्त समिति, डॉ.अंजना सोलंकी सदस्य प्रबंध समिति, प्रो. के.सी.कोठारी सदस्य प्रबंध समिति, प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक झाबुआ बैंकिंग प्रतिनिधि, डॉ. गोपाल भूरिया प्रभारी जन भागीदारी समिति उपस्थित थे।

बैठक में अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा जनभागीदारी समिति के समक्ष 11 बिन्दुओं पर चर्चा की गई। जिसमें बीएससी कम्प्यूटर साईस, महाविद्यालयनी जन भागीदारी मद से तीन अतिथि विद्वानों को रखा जाना, महाविद्यालय स्ववित्तीय योजना में सर्टीफिक्रेट कोर्स इन पाल्ट्री फार्मिंग में एक अतिथि विद्वान रखा जाना, वनस्पति विज्ञान में प्रयोग शाला तकनीशियन रखा जाना, दो प्रयोग शाला तकनीशियन रखा जाना, एक टायपिस्ट रखा जाना, एक चौकीदार रखा जाना, एक दैनिक मजदूरी पर मजदूर रखा जाना, साफ सफाई हेतु एक स्वीपर को रखा जाना, महाविद्यालय में रिपेरिंग कार्य करवाना। महाविद्यालय में इन्वेटर क्रय करना। महाविद्यालय में उपकरण क्रय करना, दो एल.ई.डी. एवं सीसीटी कैमरे लगाना, महाविद्यालय में विद्युत व्यवस्था आदि के कार्यो की समीक्षा की गई एवं इस संबंध में सम्मानीय सदस्यों से अपना अभिमद प्राप्त किया गया। मिश्रा ने संबंधित एजेंसी को कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

भाजपा मंडल झाबुआ द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन आज

माही की गूंज, झाबुआ।

भाजपा मंडल झाबुआ द्वारा 23 सितंबर, गुरूवार को स्थानीय विवेकानंद कॉलोनी स्थित शासकीय बुनियादी हाईस्कूल पर सुबह 10.30 बजे से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें सेवाभावी चिकित्सक डॉ. अरविन्द दातला एवं उनकी टीम द्वारा रोगियों का उपचार कर आवष्यक परामर्ष देने के साथ गोली-दवाईयों का वितरण भी किया जाएगा।

जानकारी देते हुए भाजपा मंडल झाबुआ मीडिया प्रभारी प्रियंक तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय सांसद गुमानसिंह डामोर, भाजपा के प्रदेष कार्यकारिणी सदस्य ओमप्रकाष शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक, जिला महामंत्री सोमसिंह सोलंकी सहित अन्य जिला पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल झाबुआ अध्यक्ष अंकुर पाठक एवं महामंत्रीद्वय जुवानसिंह गुंडिया तथा पपीष पानेरी करेंगे। षिविर दोपहर 2 बजे तक चलेगा। आयोजक भाजपा मंडल झाबुआ के पदाधिकारियों में मंडल उपाध्यक्ष अमित शर्मा, शोभा राकेष कटारा, ओम भदोरिया, किषोर भाबोर, मंडल मंत्री राजेष थापा (राजूभाई), कोषाध्यक्ष नरेन्द्र राठौरिया, आईटी सेल संयोजक विपिन गंगराड़े, रवि थापा आदि ने षिविर को सफल बनाने की अपील शहर की समस्त जनता से की है।

नगरपालिका झाबुआ की ऐतिहासिक उपलब्धि

कलेक्टर के प्रयास से मुआवजे की राशि 2.70 करोड़ प्राप्त

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर सोमेश मिश्रा के अथक प्रयास से नगरपालिका झाबुआ को मुआवजे की राशि 2.70 करोड़ प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि 135 किसानों की 24 हैक्टर भूमि डुब में आ रही थी जो विगत पांच वर्षो से मुआवजे की राशि के अभाव में डेम पूर्ण क्षमता से भर नहीं पा रहे थे। इस डेंम की क्षमता 110 एमसीएफटी है। जिसे मात्र 30 से 35 एमसीएफटी तक ही भर पा रहे थे। इस मुआवजे की राशि 2 करोड़ 70 लाख नगरपालिका झाबुआ को प्राप्त हो गए। इस अवसर पर नगरपालिका झाबुआ की अध्यक्ष मन्नू बेन डोडियार एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी एल.एस.डोडिया द्वारा कलेक्टर का आभार पुष्पगुच्छ के माध्यम से किया गया।

बांस शिल्प कलाकार को सम्मानित किया

माही की गूंज, झाबुआ। आज जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन के द्वारा कलात्मक हस्तशिल्प बांस कारीगरी का प्रदर्शन करने वाले कलाकार नटवर धोकिया की कला को सम्मानित किया।

जैन द्वारा कलाकार धोकिया की कला से प्रभावित होकर हथकरघा विभाग की कोशल विकास योजना में प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षक बनाया गया है। धोकिया द्वारा हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पंचायत ने दिया नोटिस, भाजपा नेता ने हटाया स्वेच्छा से अतिक्रमण

अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन की दोहरी नीति हुई उजागर

माही की गूंज, बामनिया।

विगत दिनों ग्राम के मुख्य चोराहे पर ट्रैफिक की समस्या से निजाद दिलवाने के उद्देश्य से गाँव मे राजस्व अमला पहुँचा था, जिसने ग्राम के चौराहे पर लगने वाली दुकानो का स्थान परिवर्तन कर रतलाम रोड पर शिफ्ट किया था। इस दौरान सवारी टेम्पुओ के मनमाने स्थान पर खड़े रहने की समस्या भी सामने आई, जिससे निजाद दिलवाने के लिए रतलाम रोड पर शासकीय भूमि पर किए अतिक्रमण को हटाकर टेम्पू स्टेण्ड बनाने की पहल की गई। मौके पर आई टीम ने ग्राम पंचायत को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने को कहा था लेकिन एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अतिक्रमण नही हटाया जा सका।

नोटिस के बाद भाजपा नेता ने स्वेच्छा से हटाया अतिक्रमण

ग्राम पंचायत ने रतलाम रोड की शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर बैठे सभी लोगो को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस थमाया। अकसर देखा गया है कि, अतिक्रमणकताओ में सत्ता से जुड़े लोग हो तो वे ऐसी मुहिम को रोकने के लिए आगे आते है पर यहां मामला उल्टा हुआ। अतिक्रमण के नोटिस से सबसे पहले भाजपा नेता और भाजपा जिला कार्यकारिणी सदस्य गुड्डू परिहार ने स्वेच्छा से अपना अतिक्रमण हटाकर प्रशासन से बाकी का अतिक्रमण हटाकर टेम्पू स्टैंड बनाने की मांग की। भाजपा नेता द्वारा अतिक्रमण हटाने की शुरुआत करने के बाद भी न तो अन्य अतिक्रमणकार्ताओ ने अतिक्रमण हटाया न ही ग्राम पंचायत और प्रशासन ने कोई मुहिम चलाई।

अतिक्रमण हटाने के नाम पर कहीं वसुली तो नही

ग्राम पंचायत के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी करवाने के कुछ ही दिन में प्रशासन की भाषा पूरी तरह बदल गई और अतिक्रमण हटाने के बड़े-बड़े दावे करने वाला प्रशासन अतिक्रमणकार्ताओ को अब सहयोग करता नजर आने लगा है। अतिक्रमण हटाने को लेकर मौनधारण कर लिया। वही ग्राम पंचायत ने भी अपनी मुहिम प्रशासन से सहयोग नही मिलने की बात कह कर ढीली कर दी, जिससे प्रतीत

होता है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन और पंचायत ने वसुली अभियान में डुबकी लगाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया।

भाजपा नेता परिहार का कहना है कि, मैने नोटिस के बाद स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लिया है, अब प्रशासन और ग्राम पंचायत अपने नोटिस का पालन करवाये, यदि वो ऐसा नही करते तो मैं इस बार पक्का अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण करूंगा।

पोषण आहार और स्वच्छता की दी जानकारी

माही की गूंज, झाबुआ।

शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ की राष्ट्रीय सेवा योजना की संयुक्त इकाई द्वारा पोषण माह के अंतर्गत ग्राम कांगझर मे जाकर पोषण संबंधी जानकारी दी और मास्क वितरित किए। साथ ही स्वक्छता के प्रति भी ग्रामीणों को जागरुक किया। पोषण माह मनाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करना है। इस जागरूकता अभियान में मुख्य रूप से एनएसएस अधिकारी प्रो. मुकामसिंह चौहान, डॉ. संगीता मसानी भाबोर एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. अंजना मुवेल, डॉ. संजू गांधी, प्रो. जेएस भूरिया, प्रो. दिलीपकुमार राठौर. प्रो. जैमाल डामोर, प्रो. अजय कुमार सहित स्वयं सेवक शामिल थे।

ट्रांसजेण्डर को पहचान पत्र वितरित

माही की गूंज, झाबुआ। समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अतंर्गत उभयलिंगी व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु झाबुआ जिले ने पहल करते हुए दिनांक 21 सितंम्बर 2021 को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में पहचान पत्र का वितरण कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया। इस अवसर पर उभयलिंगी (ट्रांसजेण्डर) समुदाय के नसीम जान, आलिया जान, रीटा जान, और रमीला जान को पहचान पत्र के साथ-साथ खाद्यन्न सुरक्षा योजना 2013 अंतर्गत पात्रता पर्ची का वितरण भी किया गया, अब तक जिले में 07 उभयलिंगी (ट्रांसजेण्डर) को पहचान पत्र जारी किये जा चुके हैं । उक्त कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री जे.एस. बघेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सिद्वार्थ जैन, अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उप संचालक सामाजिक न्याय श्री दिनेश वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री एल.एस. डोडिया, सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी सुश्री निधी ठाकुर आदि उपस्थित थें ।

चाय नाश्ते और कंबल से ज्यादा जरूरी है आवेदकों के आवेदन का निराकरण

पहले भी जनसुनवाई में हो चुके है चाय के चोचले

आवेदकों को मस्खा लगाने की बजाय अधिकारियों को फटकार लगाकर निराकरण करवाए कलेक्टर

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मील मंसूरी

राज्य शासन द्वारा कोविड संक्रमण के चलते जनसुनवाई बंद कर दी गई थी। अब जबकि स्थिति सामान्य होती नजर आ रही है तो शासन के पुनः निर्देशानुसार पिछले मंगलवार से जनसुनवाई कार्यक्रम पुनः शुरू की गई। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने खुद जनसुनवाई में आने वाले आवेदकों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। आवेदकों को प्रशासन की ओर से चाय-नाश्ता भी कराया गया और आने वाले ठंड के मौसम के लिए अभी से कंबलों का वितरण किया गया, ऐसा नहीं है कि यह सबकुछ जनसुनवाई में पहली बार हुआ है। इससे पहले भी जनसुनवाई में चाय के चोचले हो चुके है। आवेदकों के लिए नित नए प्रयोग किए गए है, मगर चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी की तरह स्थिति ढाक के तीन पात ही नजर आती है।

अब कलेक्टर मिश्रा का यह प्रयोग पिछले कलेक्टरों की तरह कहां तक जाता है यह देखने का विषय होगा। मगर इन सबके बीच एक अहम मुद्दा यह भी है कि, आवेदकों के आवेदनों का निराकरण कब और कितने समय में होगा...? कोविड संक्रमण के बाद शुरू हुई जनसुनवाई में मात्र 11 आवेदन ही आए है। जबकि यह जनसुनवाई कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तो हालात कुछ ऐसे थे कि, आवेदकों की लंबी -लंबी कतारें लगा करती थी। जनसुनवाई के शुरूआती दौर में आवेदक लाइन लगाकर कलेक्टर कक्ष के बाहर असुविधाओं के बीच खड़े रहा करते थे। जैसे -जैसे जिले में कलेक्टर बदलते गए व्यवस्थाओं में भी बदलाव होता गया। किसी ने आवेदकों के बैठने और पंखे की सुविधा उपलब्ध कराई तो किसी ने जनसुनवाई का स्थान बदल कर सुविधाओं में परिवर्तन किया। पहले जनसुनवाई में आवेदकों को निपटारा कार्ड दिया जाता था, सुनवाई की सारी व्यवस्थाएं मिन्यूअली थी। जिसके बाद सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया। आवेदकों के आवेदन की इंट्री ऑनलाइन होने लगी। मगर मिन्यूअली व्यवस्था और ऑनलाइन व्यवस्था में कोई खास फर्क महसूस नहीं किया गया। पहले भी आवेदक निपटारा कार्ड लेकर भटकते ही रहते थे और अब भी ऑनलाइन मिली पर्ची लेकर भटकते ही रहते है। ऐसे कई उदाहरण है जो आज भी पर्ची लेकर अपने निराकरण के लिए भटक रहे है। सुनवाई का सिस्टम ऑनलाइन होने के चलते स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि आवेदक की शिकायत का कब निराकरण हो जाता उसे खुद ही पता नहीं चलता मगर शिकायत के हालात जस के तस बने रहते है।

अब चूंकि कलेक्टर मिश्रा का यह पहला मौका है तो उम्मीद की जा सकती है कि, चाय के चोचले के साथ वे पूर्व कलेक्टरों की तरह भेड़ चाल न चलकर आवेदकों की शिकायतों को ज्यादा तवज्जों देंगे और शिकायतों का निराकरण कर आमजन में जनसुनवाई के प्रति धुमिल हो चुके विश्वास को जगाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो सच मानिये कलेक्टर मिश्रा बधाई के पात्र होकर आमजन के हीरो ही कहलाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि, कलेक्टर मिश्रा शिकायतों से संबंधित विभाग व अधिकारियों पर नकेल कसे। क्योंकि जनसुवाई को लेकर अब आमजन में वह उत्साह नहीं है जो पहले कभी हुआ करता था। आमजन को पहले जनसुनवाई से काफी उम्मीदे हुआ करती थी लेकिन लचर व्यवस्थाओं और अधिकारियों की लापरवही के कारण यह विश्वास अब बहुत थोड़ा ही बचा है। यही वजह है कि जनसुनवई में आवेदनों की संख्या दो अंकों में ही सिमट कर रह गई है।

जनसुवाई के आवेदकों की शिकायत के निराकरण के लिए कलेक्टर को यहीं से शुरूआत करनी चाहिए। संक्रमण काल के बाद शुरू हुई जनसुनवाई में कम ही आवेदन आ रहे है, तो इनका निराकरण भी जितनी जल्दी संभव हो कर देना चाहिए। इससे आमजन का विश्वास जनसुनवाई के प्रति जगाने का प्रथम प्रयास किया जा सकता है। आगे धीरे-धीरे ही सही मगर शिकायतों का निराकरण होता रहा तो जनता में फिर से विश्वास पैदा हो सकेगा।

संक्रमण काल के बाद शुरू हुई जनसुनवाई में कलेक्टर मिश्रा ने यह भी निर्देश दिए कि प्रति मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहकर अपने क्षेत्र के आवेदन प्राप्त करेंगे। देखा जाए तो यह निर्देश कलेक्टर के नहीं अपितु यह नियम है जनसुनवाई के। इससे पहले कई कलेक्टर इसको लेकर एक्शन मूड में भी दिखाई दिए है। हर कार्यालय के बाहर जनसुनवाई का दिन और समय लिखि तख्ती लगाने के भी निर्देश जनसुनवाई के नियमों में है। लेकिन अब शायद ही ऐसा कोई विभाग होगा जहां यह तख्ती लगी मिले। जनसुनवाई के नियमों को लेकर जब-जब किसी कलेक्टर ने सख्ती की तब-तब यह तख्तियां कार्यालयों के बाहर टांग दी गई। जैसे ही कलेक्टर की रवानगी होती वैसे ही यह तख्तियां भी अपने पुराने ठिकाने तक पहुंच जाती। इसका विपरीत असर यह देखने को मिलता कि शिकायत को लेकर आमजन संबंधित विभाग या अधिकारी के पास न जाते हुए सीधा कलेक्टोरेट पहुंचता। फिर चाहे उसे शिकायत करने के लिए कितने ही किलोमीटर का सफर क्यों न करना पड़े। वैसे तो आमजन की शिकायत सुनने के लिए पंचायत स्तर तक के प्रावधान है, लेकिन हालात यह है कि जिले में अब भी कई पंचायतें ऐसी है जिनके पंचायत भवन के ताले महीनों नहीं खुलते। उसके उपर जनपद पंचायत में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। जब शिकायतकर्ता जनपद स्तर के कार्यालय पहुंचता तो उसे या तो टाल-मटोल कर रवाना कर दिया जाता या सीधे जिला मुख्यालय पहुंचने की सलाह दे दी जाती। जिले के किसी भी तहसील कार्यालय या अनुविभागीय अधिकारी राज्य कार्यालय में भी अब तक जनसुनवाई के कम ही किस्से सुनने को मिले है। आवेदक के पास भी आखिर में एक ही विकल्प बचता है जिला मुख्यालय का कलेक्टोरेट कार्यालय। वहां भी उसे इस बात की गारंटी नहीं मिलती कि समस्या का निराकरण हो ही जाएगा।

अब कलेक्टर को चाहिए कि वे संक्रमण के बाद शुरू हुई इस जनसुनवाई में दिए गए निर्देशों को अमली जामा पहनाए और प्रति मंगलवार को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहकर अपने क्षेत्र के आवेदन प्राप्त कर उनके निराकरण के लिए नकेल कसते हुए प्रयास करें। ताकि दूर-दराज के ग्रामीण आमजन को जिला मुख्यालय तक सफर करने के लिए आर्थिक दंश न झेलना पड़े।

बिजली विभाग ने दिया जोर का झटका

बावड़ी पंचायत को 6 लाख से ज्यादा बिजली बिल बकाया भरने के लिए थमाया नोटिस

माही की गूंज , पेटलावद ।

आम व्यक्ति के अगर दो माह के बिल बकाया हो जाये तो विभाग के कर्मचारी कनेक्शन काटने के लिए पहुँच जाते है। लेकिन बात जब सरकारी उपक्रम की आती है तो लाखों रुपये का बिल बकाया होने के बाद भी वसुली नही करते और जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो लाखों रुपये के बकाया बिल के लिए नोटिस दिया जाता है, जिसे बाद में सेटलमेंट के नाम पर लेंन-देंन कर निपटा दिया जाता है। मामला ग्राम पंचायत बावड़ी का है जहां विधुत वितरण कम्पनी के सारंगी केंद्र से पंचायत को स्टेट लाइट और नलजल योजना के लिए ग्राम पंचायत के कनेक्शन पर सितंबर माह 2021 तक के 6,02,620/- रुपये बकाया बिल भरने का नोटिस थमाया है। बिजली विभाग की और से जारी नोटिस के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कई महीनों से स्टेट लाईट और नलजल योजना का बिल नही जमा किया है और बिल नही भरने की स्थिति में कनेक्शन काटने की बात कही है। बिल देख कर ग्राम पंचायत की जमीन खसक गई , ग्राम पंचायत सचिव रायचन्द गामड का कहना है कि, बिजली विभाग द्वारा हमको ज्यादा बिल दिया जा रहा है जो बिल पहले दस से बारह हजार रुपये महीना आता था वो अब विभाग द्वारा चालीस हजार रुपये महीना दिया जा रहा है , हमने सारंगी बिजली विभाग के कार्यालय पर आवेंदन देकर बिल सुधार की मांग की है।

आए दिन हो रहे हादसों का जिम्मेदार कौन?

माही की गूंज, काकनवानी। नरेश पंचाल

दिल्ली-मुंबई 8वे हाईवे का काम इन दिनों जोरों से चल रहा है, जहां-जहां से हाईवे निकल रहा है, मैन रोड की क्रॉसिंग पर जो पुलिया बन रहे हैं जिस कारण आए दिन लोग हादसे का शिकार होते जा रहे हैं जिसे देखने वाला कोई नहीं है। जिस मेन रोड पर पुलिया बनाए जा रहे हैं उस मैन रोड से वाहन निकलने के लिए डायवर्सन दिया जाता है जिसे डामरीकरण के साथ बनाने का प्रावधान है, लेकिन बिना मापदन्ड का कच्चा डायवर्सन बना दिए, 8 वें हाईवे लाइन के ठेकेदारों की मनमानी एवं हठधर्मिता के कारण लोग आए दिन हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। डायवर्सन वाला रोड मिट्टी से लथपथ गड्डेदार पानी भरा होता है अभी बारिश का टाइम चल रहा है काफी कीचड़ एवं चिकनी मिट्टी होने के कारण आए दिन सैकड़ों बाइक वाले गिरते रहते हैं, जिन्हें नुकसान पहुंचता है। काकनवानी से 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम चोखावाडा में मैन रोड पर जो पुलिया बनाया जा रहा है उस पुलिया के पास से ही डायवर्सन दिया गया है, जहां बिना डामरीकरण के ही मिट्टी डालकर डायवर्सन बना दिया गया। इस रोड पर सैकड़ों वाहन रोजाना गुजरते है, वही ये रोड गुजरात को भी जोड़ता है। लेकिन ठेकेदारों की मनमानी से रोजाना यहां सैकड़ों मोटरसाइकिल वाले एवं राहगीर गिरते पड़ते इस रोड से निकलते हैं ,मगर इस और प्रशासन का भी कोई ध्यान नहीं जा रहा है।

ग्राम वासियों का कहना है कि, ठेकेदार अपनी मनमानी चला रहा है और यहां सैकड़ों लोग रोज गिरते हैं इस डायवर्सन को सही तरीके से डामरीकरण किया जाए तो लोग हादसे का शिकार नहीं होंगे, यहां पुल बन रहा है डायवर्सन भी जस्ट उसके पास से ही निकाला गया जिससे बन रहा पुल का काम ऊपर से अगर कोई लोहा या कोई वस्तु गिरी तो उससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुल निर्माण के पास करीब 500 मीटर की दूरी पर एक मंदिर भी है जहां सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए रोजाना आते हैं जिन्हें भी इस कीचड़ युक्त रोड से ही गुजर कर आना-जाना पड़ता है। इस रोड को लेकर यहां कई बार विवाद भी हो चुका है ठेकेदार लोग जमीन मालिक के बिना परमिशन के ही जमीन हथिया रहे हैं, जमीन मालिक के कुछ कहने या बोलने पर ठेकेदार के गुंडे लोग आए दिन भोले-भाले आदिवासियों को मार-मार कर भाग जाते है, भागने के बाद पुलिस में जाकर खुद ही झुटी रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और यहां के लोगों को फसाया जाता है। ऐसी कई घटना हो चुके हैं जिन्हें पुलिस रिपोर्ट के बाद आपसी समझौता करवाया गया है, आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा... यह समझ से परे है।

नवरत्न परिवार द्वारा इस वर्ष का महाधिवेशन होगा माँ गंगा के तट पर

माही की गूंज, बामनिया।

जिनशाशन की सेवा करने व युवाओ को प्रेरित कर शक्ति का सदुपयोग कर आगे सपना सजोने वाले परम पूज्य आचार्य भगवन तीर्थोउधारक मालवा भूषण महान तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री नवरत्न सागर सूरीश्वर जी द्वारा सकल जैन समाज को संघठित कर नवरत्न परिवार का गठन परमपूज्य आचार्यश्री विश्व सागर सुरेश्वर जी द्वारा 12 वर्ष पूर्व नागेश्वर तीर्थ धाम पर कार्यकारणी का गठन किया गया था। जिसमे जिनशाशन ने प्रभावक कार्य कर नए-नए आयामो को छुआ। नवरत्न परिवार द्वारा इस वर्ष का महाधिवेशन माँ गंगा के तट पर देवभूमि हरिद्वार में 25 सितम्बर को आयोजित किया जा रहा, जिसमे समाज के उत्थान युवा शक्ति को संघठित कर समाज मे सेवा करने के उद्देश्य से भारत भर के युवा भाग लेंगे, जिसमे पेटलावद, रायपुरिया ,बामनिया,सारंगी के करीब दो सौ से अधिक सदस्य हरिद्वार जा रहे है।

बामनिया श्री संघ द्वारा हरिद्वार जा रहे यात्रियों का बामनिया में स्वागत किया गया, जिसका लाभ मंगलेश भंडारी परिवार द्वारा लिया गया। सकल संघ पदाधिकारी मंगलेश भंडारी, भंवरलाल बाफना, संजय लुणावत, स्पर्श लुणावत, सीमा भंडारी, सुनीता लुणावत, ज्योति लुणावत आदि उपस्थित थे। संघ के प्रमुख पेटलावद निवासी सुरेंद्र भंडारी, प्रकाश भंडारी, रायपुरिया के सुनील मालवी ने बामनिया श्री संघ के पदाधिकारियों का बहुमान किया।

आचार्य सम्राट डॉ. शिव मुनि मसा का आगामी चातुर्मास सूरत में होगा

माही की गूंज, बामनिया ।

ध्यान योगी चतुर्थ पठधर आचार्य सम्राट परम पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणा आठ का आगामी 2022 का चातुर्मास द्रव्य क्षेत्र काल भाव का आगार रखते हुए धर्म नगरी सूरत सिटी को प्रदान किया गया। उक्त जानकारी श्री अखिल भारती जैन दिवाकर संघठन समिति के मार्गदर्शक भंवरलाल बाफना ने देते हुए बताया कि, लब्धि पार्श्वनाथ तीर्थ धाम में आयोजित आत्म शुक्ल शिव प्रकाश उत्सव में आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य श्री के मुखारविंद से हुक्मीचंद कोठारी की अध्यक्षता में गठित समिति की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डायमंड सिटी सूरत महासंघ को प्रदान किया गया । आचार्य श्री की इस घोषणा से पूरे क्षेत्र में विशेषकर गुजरात महाराष्ट्र-सौराष्ट्र और मध्यप्रदेश के लाखों भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई।

स्कूलो में बच्चों की उपस्थिती अपेक्षाकृत कम

माही की गूंज, थांदला।

कोरोना काल के 17 माह बाद शासन ने प्राथमिक स्तर के स्कुलो को बच्चो के लिए खोलने के आदेश के पश्चात सोमवार से आधी क्षमता के साथ प्राथमिक स्तर के भी विद्यालय प्रारंभ किए गये, स्कुलो के खुलने पर बच्चो की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रही। शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र सभी जगह बच्चो की संख्या 2 दर्जन से अधिक नही मिली। कई स्कूलो में बच्चे आये ही नही तथा कई स्कुलो मे चार-पाच बच्चे ही उपस्थित रहे। प्राथमिक स्कुलो के खुलने के साथ ही उनसे जुडी समस्याए भी दिखाई दी। स्कुलो की छतो से टपकता पानी, जर्जर भवन, मध्यान्ह भोजन संबधी परेशानिया ऐसी अन्य कई परेशानियो से शिक्षको और बच्चो को रूबरू होना पड रहा है। प्रशासन ने स्कूल खोलने के आदेश तो दे दिए, लेकिन काफी समय से बंद स्कूलो और उनसे जुडी समस्याओ की ओर कोई ध्यान नही दिया। स्कूलो मे कम उपस्थिति के संबध मे शिक्षको का कहना था कि, बच्चो के पालको को मोबाईल द्वारा सूचना दी गई थी। कुछ पालको के पास मोबाईल नही हाने से बच्चो तक सूचना नही पहुच पाई। कुछ का कहना था कि, अभी स्कूल खुली है इसलिए उपस्थिति कम है कुछ दिन में बच्चे की संख्या बड सकती है। ग्रामीण क्षेत्रो मे कई छोटे बच्चे घर के कामो और मवेशी चराने के काम मे व्यस्त देखे गए। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलो मे मध्यान्ह भोजन योजना मे वितरित किए जाने वाली सामग्री संबधी शिकायते भी मिली। ग्राम जुलवानिया बडा के पटेल फलिये की स्कूल मे पिछले 2 वर्षो से आंगनवाडी संचालित हो रही है पर अब आंगनवाडी कहा संचालित हो रही है इसकी जानकारी नही मिल पाई। नगर के एक प्राथमिक शाला मे 89 बच्चे दर्ज है, गाइडलाईन के मुताबिक 45 बच्चे स्कूल पहुचना थे, किन्तु पहुचे केवल 15 से 20 बच्चे आ रहे है। बच्चो के लिए स्कूलो मे सेनेटाईजर मास्क की व्यवस्था भी नजर नही आई।

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पीएन अहिरवार ने बताया कि, स्कुलो मे उपस्थिति अपेक्षाकृत कम है, क्षेत्र मे बारिश का दौर भी जारी हे, इस वजह से भी उपस्थिति प्रभावित हुई है कुछ दिनो मे स्थितिया सुधर जायेगी।

चार वर्ष से मायके में बैठी पत्नी को किया अगवा

पुलिस नहीं कर रही अगवा करने वालों पर कार्रवाई, पिता ने लगाया आरोप

माही की गूंज, खवासा।

करीब दस वर्ष पूर्व शांतिलाल पिता भूरजी जाति मुणिया की लड़की भाना की शादी सागवा ग्राम पंचायत के ग्राम बड़ी झरिया निवासी तोलसिंग पिता बहादुर जाति माल से हुई थी। छः वर्षों में दोनों के विवाह संबंध के साथ दो संतानें हुई, तो वही पत्नी भाना पर तोलसिंह अनर्गल आरोप लगाकर डायन कह कर विवाद करता था। वही तोलसिंग एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी घर में ले आया और प्रथम पत्नी भाना को विवाद कर करीब चार वर्ष पूर्व निकाल दिया। वही दोनों संतान को पिता ने अपने पास रखा। तब से भाना अपने पिता शान्तु के पास नवापाड़ा रह रही है। करीब दो वर्ष से प्रथम पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी, पति तोलसिंग के लाने के संबंध के साथ आपसी विवाद एवं तलाक संबंधी विचारधीन प्रकरण न्यायालय में चल रहा है।

भाना अपने पिता के यहां से रविवार को परवाड़ा देवरे मंदिर पर गई थी कि, बाइक पर अन्य दो महिला के साथ अपने परिचित व्यक्ति के साथ बैठकर वापसी अपने पिता के घर जा रही थी कि, तोलसिंग अपने कुछ साथियों के साथ जीप से आया और रास्ते में मोटरसाइकिल से उतारकर भाना को जबरदस्ती अपनी चार पहिया गाड़ी में बिठा कर अगवा कर ले गया। जिसकी रिपोर्ट रविवार को भाना के पिता शान्तु के द्वारा पुलिस चौकी में दर्ज करवाई।

शान्तु ने बताया कि, तोलसिंग अपने कुछ साथियों के साथ मेरी लड़की को अगवा कर ले गया था। देर रात शराब पीकर बडी झारिया में तोलसिंग के घर आपसी में विवाद होने लगा, तथा मेरी बेटी को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया।

तोलसिंग व अन्य के साथ आपसी विवाद के चलते वहाँ तोलसिंग की दूसरी पत्नी भी आ गई और बंद कमरा खुलवाया और कहा कि, इसको क्यों लाए। वही शान्तु ने बताया, सभी के आपसी विवाद के चलते रात्रि में बचते-बचाते लड़की भाना घर पर अपनी जान बचाकर आई।

पुलिस को तोलसिंग एवं उसके साथियों के विरुद्ध मेरी बेटी को अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस अगवा करने वाले व्यक्तियों से सांठगांठ करने के साथ अगवा करने वालों पर कोई मामला दर्ज नहीं कर रही है। आगे भी मेरी बेटी भाना को तोलसिंग एवं उसके परिवार से जान का खतरा बना रहेगा।

'राष्ट्रीय पक्षी के संरक्षण को लेकर सपना अधूरा'

'आये दिन हॉइ टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत के घाट उतर रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर'

माही की गूंज, जामली। जितेंद्र राठौर

राष्ट्रीय पक्षी मोर को लेकर प्रशासन सुस्त है, ग्राम जामली के मेन रोड पर लगी हाई वोल्टेज लाइट की चपेट में आने से आए दिन हो रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत को लेकर प्रशासन सुस्त नजर आ रहा है। आए दिन हो रही राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, अधिकारी है कि सिर्फखानापूर्ति करने में लगे हुए है कोई ठोस कदम नही उठाए जा रहे हैं। गांव के आसपास हरियाली होने की वजह से दाना-पानी की चाह में गांव के आसपास लगे पेड़-पौधों पर आकर बैठ जाते है जिसकी वजह से आसपास लगे हाई वोल्टेज लाइट की चपेट में आ जाते हैं। दो-तीन साल के अंतराल में कई मोर की मौत हो जाने के बाद प्रशासन के अधिकारियो के द्वारा आकर मौका मुआयना भी किया, जहां पर आकर पंचनामा बनाया गया था लेकिन उसको लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। राष्ट्रीय पक्षी मोर को लेकर प्रशासन कितना जागरूक है अब देखने वाली बात यह है कि, जब एक से दो रोज पहले भी राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो चुकी है इनके संरक्षण को लेकर क्या उपाय किया जाता है अब ये देखने वाली बात है।

मयूर पार्क का सपना अधूरा है जिसको लेकर युवाओं द्वारा प्रशासन को लेकर प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था लेकिन उसको लेकर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

सीएम हेल्प लाइन पर भी की गई थी शिकायत

सीएम हेल्प लाइन पर भी की गई शिकायत की गई पर वहा से भी कोई आस नही बंधी समय रहते इस को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या दिन पे दिन कम हो जायेगी।

जिला वन अधिकारी से भी बात हुई तो, उनका कहना है' कि हमने एमपीईबी को हाई वोल्टेज लाइट सिफ्ट करने को लेकर पत्र लिखा है और जिला कलेक्टर साहब को भी निवेदन कर दिया है।

पैसा एक्ट लागू करने के लिए मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद

स्वर्गीय दिलीपसिंह भूरिया पैसा कानून के जनक है- वनवासी कल्याण परिषद

माही की गूंज , झाबुआ।

पैसा कानून को लाने का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देना है पेसा एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और कई राज्यों में लागू है देश के 10 राज्यों में यह कानून लागू है लेकिन छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश और उड़ीसा में यह पूरी तरह से लागू नहीं है इसके तहत जनजाति ग्राम सभाओं को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास के काम में अनिवार्य परामर्श को शक्ति दी गई है खदानों और खनिजों लाइसेंस पट्टा देने के लिए ग्राम सभा को सिफारिशें देने का अधिकार दिया गया है अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस कानून को राज्य में पूरी तरह से लागू करने का ऐलान कर आदिवासियों को बड़ी सौगात दी है ।अलकेश मेडा द्वारा बताया गया कि पेसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन खनिज संपदा लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा पेसा एक्ट लागू होने के बाद सामुदायिक प्रबंधन समितियां वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगे और उससे ग्राम सभा को अनुमोदित कराएंगे सामुदायिक भवन प्रबंध समिति का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को आदिवासी समाज की परंपरा रीति-रिवाज सांस्कृतिक पहचान समुदाय के संसाधन और विवाद समाधान के लिए परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाया जाएगा राज्य में तेंदूपत्ता बेचने का काम भी उन समिति करेगी।पेसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन खनिज संपदा लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा पेसा एक्ट लागू होने के बाद सामुदायिक प्रबंधन समितियां वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगे और उससे ग्राम सभा को अनुमोदित कराएंगे सामुदायिक भवन प्रबंध समिति का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को आदिवासी समाज की परंपरा रीति-रिवाज सांस्कृतिक पहचान समुदाय के संसाधन और विवाद समाधान के लिए परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाया जाएगा राज्य में तेंदूपत्ता बेचने का काम भी उन समिति करेगीपेसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन खनिज संपदा लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा पेसा एक्ट लागू होने के बाद सामुदायिक प्रबंधन समितियां वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगे और उससे ग्राम सभा को अनुमोदित कराएंगे सामुदायिक भवन प्रबंध समिति का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को आदिवासी समाज की परंपरा रीति-रिवाज सांस्कृतिक पहचान समुदाय के संसाधन और विवाद समाधान के लिए परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाया जाएगा राज्य में तेंदूपत्ता बेचने का काम भी उन समिति करेगी । पेसा एक्ट के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति वाली ग्राम पंचायतों को सामुदायिक संसाधन जैसे जमीन खनिज संपदा लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार मिल जाएगा पेसा एक्ट लागू होने के बाद सामुदायिक प्रबंधन समितियां वर्किंग प्लान के अनुसार हर साल माइक्रो प्लान बनाएंगे और उससे ग्राम सभा को अनुमोदित कराएंगे सामुदायिक भवन प्रबंध समिति का गठन भी ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा पैसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को आदिवासी समाज की परंपरा रीति-रिवाज सांस्कृतिक पहचान समुदाय के संसाधन और विवाद समाधान के लिए परंपरागत तरीकों के इस्तेमाल के लिए सक्षम बनाया जाएगा राज्य में तेंदूपत्ता बेचने का काम भी उन समिति करेगी । साथ ही आज स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जो ÷पेसा कानून के जनक÷ है आज मेघनगर पर वनवासी कल्याण परिषद द्वारा माल्यार्पण कर कालूसिंह मुजाल्दे ओर डॉ रूपनारायण मंडावे जो कि आदिम जाति कल्याण मंत्रणा परिषद मध्यप्रदेश के सदस्य है उनका आभार जिन्होंने पेसा काननू को लागू करवाने के लिए कड़ी मेहनत की साथ ही मुख्यमंत्री का भी आभार जिन्होंने पेसा कानून को मध्यप्रदेश में चरणबद्ध रूप से लागू करने का निर्णय लिया ।उपस्थित जिला संगठन मंत्री गनपत मुनिया वनवासी कल्याण परिषद झाबुआ युवा सह प्रमुख अलकेश मेडा,रेलेश सिंगार ,सिद्धार्थ भाबोर, राहुल अखड़िया, लक्ष्मण देवड़ा, कबर निंगवाल,अनिल रावत, कांजी भूरिया, पवन परमार जनजाति प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिनेश देवड़ा, धन्नू भूरिया जीराहुल अखड़िया, लक्ष्मण देवड़ा, कबर निंगवाल,अनिल रावत, कांजी भूरिया, पवन परमार जनजाति प्रमुख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, दिनेश देवड़ा, धन्नू भूरिया जी

संपादकीय

चुनाव से पहले चन्नी को मिला चुनौतियों क ताज

पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही रस्साकशी व उथल-पुथल के बाद भले ही पार्टी हाईकमान ने चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य की कमान सौंप दी हो, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि पार्टी में महत्वाकांक्षाओं का उफान थम गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद विधायक दल का नेता चुने जाने में जिस तरह से ऊहापोह की स्थिति नजर आई, उससे पता चलता है कि अभी भी पार्टी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जब पार्टी अध्यक्ष बदले जाने के बाद भी उठापटक व अनबन की सीमाएं पार होने लगीं तो पार्टी ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का मन बनाया। निःसंदेह, कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशाली को लेकर पार्टी में नाराजगी थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद यह टकराहट चौराहे पर आने लगी। बहरहाल, ऐसे वक्त में जब अकाली दल ने देश के सबसे ज्यादा दलितों वाले राज्य में बसपा से हाथ मिलाकर कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर दी थी, तो उसकी काट में कांग्रेस ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य की बागडोर सौंपकर एक मास्टर स्ट्रोक ही खेला है। नवजोत सिद्धू के बेहद करीबी माने जाने वाले और कैप्टन अमरिंदर के मुखर विरोधी चरणजीत सिंह चन्नी को सही मायनों में कांटों का ही ताज मिला है। पार्टी में जारी उठापटक को खत्म करके चन्नी पर उन वादों को पूरा करने का दबाव होगा, जिसे पूरा न करने का आरोप वे कैप्टन पर लगा रहे थे।

जाहिर-सी बात है कि, पार्टी का उन पर दबाव रहेगा कि वे 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सत्ता में वापसी करें। यह तभी संभव है जब पार्टी में मनभेद का पूरी तरह पटाक्षेप हो। पंजाब की सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाने वाले मालवा क्षेत्र से आने वाले चन्नी पार्टी की सत्ता में वापसी करा पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी ओर अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि, वे पार्टी में रहेंगे या कोई अन्य बड़ा फैसला लेंगे। वहीं पार्टी में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद टिकट बंटवारे के विवाद भी सामने आएंगे। यदि पार्टी के गुटों की रस्साकशी पर विराम लग पाएगा तभी चन्नी की राह निष्कंटक हो पायेगी। बहरहाल, चन्नी के पास समय कम है और पार्टी को चुनाव में लड़ने लायक बनाने का काम ज्यादा है। वे लगातार कैप्टन सरकार पर पिछले चुनाव में किए गए वादे पूरा न करने का आरोप लगाते रहे हैं, जिसमें बेअदबी के दोषियों को सजा दिलाने, अवैध खनन और नशे की तस्करी पर अंकुश लगाने, सस्ती बिजली और सबसे बढ़कर किसान आंदोलन से उपजी चुनौतियां शामिल हैं। कांग्रेस हाईकमान ने इस सीमावर्ती व संवेदनशील राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का जोखिम तो उठाया है लेकिन इसका परिणाम तो अगले वर्ष फरवरी में होने वाले चुनाव के बाद ही सामने आयेगा। सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि, नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी में कितनी एकजुटता कायम रह पाती है। जनता में एक संदेश यह भी जा सकता है कि, पार्टी को एक दशक के वनवास के बाद मुश्किल हालात में सत्ता में वापसी दिलाने वाले वरिष्ठ व अनुभवी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सम्मानजनक विदाई नहीं हुई। वहीं इस बदलाव का एक निष्कर्ष यह भी है कि, पार्टी में ऐसे जनाधार वाले नेताओं का वक्त नहीं रहा जो गांधी परिवार के सुर में सुर न मिलाएं। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक में पार्टी क्षत्रपों का टकराव इसी सोच को उजागर करता है। यही वजह है कि, कैप्टन को इस्तीफा देने के बाद कहना पड़ा कि उन पर अविश्वास जताया जा रहा है और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। बहरहाल, अब जब नवजोत सिद्धू के करीबी चन्नी को सत्ता की बागडोर मिल गई है तो कयास इस बात को लेकर भी है कि, यदि पार्टी की सत्ता में फिर वापसी हो पाती है तो आगे राज्य की बागडोर चन्नी के हाथ में रहेगी या सिद्धू को बैटिंग करने का अवसर मिलेगा।

संकट से मुकाबले के रणनीतिक विकल्प

डॉ. भरत झुनझुनवाला
आर्थिक विशलेषक

तालिबान और पाकिस्तान के गठबंधन की कश्मीर पर निगाह है। ये दोनों पूरी तरह आपस में गुंथे हुए हैं। हमें तय करना है कि, इस गठबंधन का सामना करने के लिए हम अमेरिका का साथ लेंगे अथवा चीन का? एक संभावना यह है कि, भारत और अमेरिका तालिबान-पाकिस्तान और चीन के गठबंधन का सामना करें। दूसरी संभावना है कि, भारत और चीन मिलकर तालिबान-पाकिस्तान के गठबंधन का सामना करें। आज विश्व का सामरिक विभाजन अमेरिका और चीन के बीच है। हम अमेरिका का साथ देंगे तो अमेरिका के दुश्मन चीन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी कि वह तालिबान एवं पाकिस्तान के साथ जुड़े। यों भी चीन के पाकिस्तान के साथ मधुर सम्बन्ध हैं, इसलिए चीन का झुकाव मूल रूप से तालिबान-पाकिस्तान की तरफ होगा। लेकिन यह गठबंधन हमारे लिए कष्टप्रद होगा क्योंकि तब हमारे पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक तालिबान-पाकिस्तान-चीन के गठबंधन द्वारा हम घेर लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान-तालिबान के गठबंधन को चीन की आर्थिक सहायता मिल जाएगी तो वह ताकतवर हो जायेगा। इसलिए हमें दूसरी संभावना पर विचार करना चाहिए कि, भारत और चीन मिलकर तालिबान-पाकिस्तान के गठबंधन का सामना करें। यह संभावना वर्तमान में कठिन दिखती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। कारण यह कि चीन को पाकिस्तान से जो लगाव है, वह मुख्यतः वाणिज्यिक है। यदि चीन को भारत से वाणिज्यिक और व्यापारिक लाभ मिलता है तो चीन को भारत से बेहतर रिश्ते कायम करने में कठिनाई नहीं होगी। उस स्थिति में भारत पाकिस्तान और तालिबान के गठबंधन का सामना कर सकेगा। अतः हमें अमेरिका और चीन के बीच अपने सहयोगी का चयन करना है। अपने सहयोगी को चिन्हित करने के लिए सर्वप्रथम उसकी ताकत को आंकना जरूरी है। इसमें कोई संशय नहीं कि, बीते 100 वर्षों में विश्व के अधिकांश तकनीकी आविष्कार पश्चिमी देशों अथवा अमेरिका द्वारा किए गए हैं। ये आविष्कार ही अमेरिका की ताकत हैं। जैसे परमाणु बम, जेट हवाई जहाज, सुपर कम्प्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट इत्यादि। ये सभी आविष्कार अमेरिका द्वारा किए गए। लेकिन बीते दो दशक में चीन ने तकनीकी क्षेत्र में भारी प्रगति की है। चीन ने स्वयं अपने लड़ाकू विमान बनाए हैं और इन्हें अन्य देशों से नहीं खरीदा है। उन्होंने परमाणु अस्त्र बना लिए हैं, मंगल ग्रह पर अमेरिका की बराबरी में अपने यान को उतारा है और अमेरिका से आगे बढ़कर सूर्य के बराबर का तापमान अपनी प्रयोगशाला में बनाया है। चीन के जूम और कैम स्कैनर जैसे एप प्रतिबंधों के बावजूद भारत और अमेरिका में पूरी तरह व्याप्त हैं। इसलिए पूर्व में अमेरिका ने जो भी तकनीकी महारत हासिल की थी, वह वर्तमान में फिसल गई है। आज चीन और अमेरिका तकनीकी दृष्टि से बराबर दिखते हैं। इसलिए तकनीकी आधार पर हम अपने मित्र का चयन नहीं कर सकते। चीन की आर्थिक ताकत भी अमेरिका के बराबर पहुंच चुकी है। सहयोगी चयन करने का एक आधार सामरिक है। अमेरिका के भारत पर कई उपकार हैं, द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री विन्सेंट चर्चिल अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट से मिलने अमेरिका गए थे। उन्होंने रूजवेल्ट को विश्वयुद्ध में इंग्लैण्ड की मदद करने का आग्रह किया। बताते हैं कि, रूजवेल्ट ने मदद देने की एक शर्त यह रखी कि इंग्लैण्ड को भारत जैसे अपने उपनिवेशों को स्वतंत्र करना होगा। हम मान सकते हैं कि, रूजवेल्ट का वह दबाव भी इंग्लैण्ड द्वारा भारत को स्वतंत्रता दिलाने में कुछ हद तक कारगर रहा होगा। इसके बाद 60 के दशक में अमेरिका ने भारत को पब्लिक लॉ 480 के अंतर्गत मुफ्त अनाज भारी मात्रा में उपलब्ध कराया था। उस समय हमारे देश में सूखा पड़ गया था और हम भुखमरी के कगार पर आ गए थे। अमेरिका के इन उपकारों को मानते हुए हमें अमेरिका के दूसरे पक्ष को भी देखना होगा। अमेरिका ने सऊदी अरब में लोकतंत्र विरोधी सरकार का निरंतर साथ दिया है, पाकिस्तान को एफ16 लड़ाकू विमान समेत तमाम सहायता दी है, जिनका उपयोग पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ किया जा सकता है, अफगानिस्तान सरकार को जिस प्रकार अमेरिका छोड़ कर भागा है, उससे विश्वास कम ही पैदा होता है। पूर्व में दक्षिण वियतनाम में भी ऐसा ही हुआ था। अतः अमेरिका का अपने साथियों के प्रति व्यवहार भी बहुत आशाजनक नहीं रहा है। हाल ही में यूरोपीय देशों के प्रमुख ने कहा है कि, अब यूरोपीय देशों को विश्वस्तर पर सैन्य गतिविधियां करने के लिए अमेरिका के इतर अपनी ताकत को बनाना होगा। इसलिए पूर्व में अमेरिका का चरित्र जो भी रहा हो, वर्तमान में अमेरिका स्थाई एवं ठोस साथी बना रहेगा, यह संदेह का विषय बना रहता है। दूसरी तरफहमारा चीन से 1962 से शुरू हुआ सरहद का विवाद लगातार जारी है। चीन ने हमको चारों तरफसे घेरने का प्रयास किया है। जैसे श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश को भारी ऋण दिए हैं। अतः हमारे सामने कुएं और खाई के बीच चयन करने जैसी स्थिति है। अमेरिका भरोसेमंद नहीं है जबकि चीन के साथ हमारा लगातार विवाद रहा है। इन दोनों विकल्पों को सैन्य दृष्टि से भी देखना चाहिए। यदि हम चीन के साथ हाथ मिलाते हैं तो भारत-चीन का गठबंधन तालिबान-पाकिस्तान के गठबंधन पर अंकुश लगाने में सफल होने की संभावना अधिक दिखती है तब तालिबान-पाकिस्तान को हम घेर सकेंगे। लेकिन इस दिशा में हमें चीन के साथ अपना सरहद का विवाद निपटाना पड़ेगा। दूसरी तरफयदि हम अमेरिका के साथ हाथ मिलाते हैं तो तालिबान-पाकिस्तान-चीन का विशाल गठबंधन हमारे सामने खड़ा होगा, जिसका सामना करना कठिन होगा। चूंकि चीन की आर्थिक ताकत इस गठबंधन को पोसेगी। अमेरिका के भरोसेमंद न होने का संकट भी बना रहेगा। इसलिए हमें चीन के साथ अपने सरहदी विवाद को निपटाना चाहिए और वर्तमान में जो बड़ा संकट तालिबान-पाकिस्तान-चीन के गठबंधन के बनने से हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसे क्रियान्वित होने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। हमें तय करना होगा कि, बड़ा दुश्मन कौन, तालिबान-पाकिस्तान या चीन? चीन के साथ हमारी दुश्मनी 1962 के युद्ध से शुरू हुई है। नेविल मैक्सवेल द्वारा लिखी पुस्तक 'इंडियाज चाइना वार' के अनुसार भारत के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने चीन को उकसाया था। उस खोजबीन में जाने के स्थान पर आगे की देखनी चाहिए। इस समय हमें चीन से कम और तालिबान-पाकिस्तान से खतरा अधिक है। इसलिए छोटे दुश्मन चीन से मिलकर बड़े दुश्मन तालिबान-पाकिस्तान का सामना करना चाहिए।

न्याय प्रणाली के भारतीयकरण की जरूरत

अनुप भटनागर

देश के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण का मत है कि, न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली का भारतीयकरण समय की मांग है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण सवाल यह जुड़ा है कि, विविधता से परिपूर्ण भारत में न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण कैसे हो। प्रधान न्यायाधीश की यह चिंता भी उचित है कि अदालतों की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होने की वजह से ग्रामीण अंचलों की जनता इसे समझ नहीं पाती हैं और वे खुद को इससे अलग-थलग महसूस करते हैं। यही नहीं, विवादों के समाधान के प्रयास में उसका धन भी ज्यादा खर्च होता है। निःसंदेह न्याय प्रणाली का भारतीयकरण तभी संभव और सफल होगा जब जिला स्तर पर लोगों को सहजता और सुगमता के साथ सस्ता न्याय मिलने लगे। इस दिशा में न्यायपालिका और केंद्र प्रयास भी कर रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का नतीजा देश में सफलतापूर्वक काम कर रही लोक अदालतें हैं, जबकि इसके विपरीत, सांध्य अदालत और ग्राम अदालत स्थापित करने के प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। भारतीयकरण के लिए जरूरी है कि, अदालतों के आदेश और फैसलों की भाषा भी सरल और आसानी से समझ में आने वाली हो। उच्चतम न्यायालय अदालतों के आदेशों और फैसलों में प्रयुक्त जटिल और पेचीदगी भरी भाषा पर लगातार चिंता भी व्यक्त कर रहा है। देश के विभिन्न राज्यों की अधिकांश अधीनस्थ अदालतों में राज्य की राजभाषा में ही कामकाज होता है जबकि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय तथा दूसरे मंचों पर न्यायिक कामकाज अंग्रेजी भाषा में होता है, जहां निश्चित ही ग्रामीण परिवेश से आए वादकारियों को इस कार्यवाही को समझने में बहुत कठिनाई होती है। ग्रामीण अंचल के निवासियों के विवादों का सुगमता और सहजता से समाधान करने के इरादे से केन्द्र ने ग्रामीण अदालतों की स्थापना का निर्णय किया था। संसद ने 2008 में ग्राम न्यायालय कानून बनाया और महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर दो अक्तूबर, 2009 को इस कानून को देश में लागू किया गया। इस कानून के तहत देश में पांच हजार से अधिक ग्राम अदालतों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। इस कानून का मकसद ग्रामीणों के विवादों को उनके गांव की सीमा में ही सुलझाना और उन्हें सुगमता से न्याय दिलाना था। परंतु ग्राम न्यायालय योजना राज्यों की उदासीनता के अभाव में अधिक कारगर नहीं हो सकी। इस महत्वाकांक्षी योजना को सफल बनाने के लिए केन्द्र से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। शीर्ष अदालत ने ग्राम अदालतों पर आने वाले खर्च की राशि बढ़ाने पर विचार करने का भी केंद्र को निर्देश दिया था। इस योजना के तहत शुरू में प्रति ग्राम अदालत भवन के लिए 10 लाख रुपए वाहन के लिए पांच लाख रुपए और कार्यालय की साज-सज्जा के लिए तीन लाख रुपए के हिसाब से सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गयी थी। इस योजना के तहत शुरू में सिर्फ11 राज्यों में 343 ग्राम न्यायालयों को अधिसूचित किया था, लेकिन राज्यों में पर्याप्त संख्या में ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं हुए। ग्राम न्यायालयों की स्थापना को लेकर नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस नाम के संगठन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ। इस मामले में न्यायालय ने राज्यों से हलफनामे पर जानकारी मांगी थी। अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले राज्यों पर न्यायालय ने जनवरी, 2020 में सख्त रुख अपनाया और उन पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। शीर्ष अदालत में यह मामला अंतिम बार 28 जुलाई 2020 को सूचीबद्ध हुआ था। इन ग्राम न्यायालयों में सिर्फउन्हीं मामलों की सुनवाई होनी थी, जिसमें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है। इन अदालतों को दीवानी और फौजदारी के सामान्य मामलों की सुनवाई के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए समझौता और अपराध कबूल करके सजा कम कराने के उपाय शामिल थे। इस कानून में यह भी व्यवस्था की गई कि, ग्राम न्यायालय के फैसले को 30 दिन के भीतर जिला अदालत या सत्र अदालत में चुनौती दी सकती है। जिला अदालत और सत्र अदालत को ऐसे मामले में छह महीने के भीतर निर्णय करने का प्रावधान भी कानून में किया गया। लेकिन यह योजना राज्य सरकारों के उदासीन रवैये के कारण सफल नहीं हो पा रही है। दरअसल, ग्राम न्यायालयों की स्थापना की धीमी प्रगति में इनके अधिकार क्षेत्र को लागू करने में पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों का ढुलमुल रवैया, नोटरी और स्टाम्प विक्रेताओं की अनुपलब्धता और नियमित अदालतों के समान अधिकार क्षेत्र की समस्या के योगदान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि, सरकार अंग्रेजों के जमाने के पुराने और अव्यावहारिक हो चुके कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया की तरह ही देशवासियों को सहजता से समझ में आने वाली कानूनी प्रक्रिया के भारतीयकरण के बारे में प्रधान न्यायाधीश के विचारों को गंभीरता से लेकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी।

मल्टी-स्टारर दमखम के सहारे कामयाबी

आलोक पुराणिक

संगीत में जोड़ियां होती थीं एक जमाने में, परम हिट भी होती थीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याणजी आनंदजी। अब तो पान-मसाले को बेचने के लिए जोड़ियां बन रही हैं। अमिताभ बच्चन और रणवीर सिंह एक पान-मसाला बेच रहे हैं, उधर शाहरुख खान-अजय देवगन भी मिल-जुलकर एक पान-मसाला बेच रहे हैं। बहुत पुराने वक्त में एक स्टार ही अपने बूते फ़िल्म कामयाब करवाया करते थे। फिर कई स्टार लोगों को लेकर फ़िल्म कामयाब बनाने का दौर चला। अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर को मिलाकर मल्टी-स्टारर फ़िल्म बनी अमर अकबर एंथोनी। अब मल्टी-स्टारर पान-मसाले भी देखने को मिलेंगे। कई सारे स्टार मिलकर एक पान-मसाले को बेचेंगे। पान-मसाले में भी अमर अकबर और एंथोनी होंगे। जोड़ी बनाकर स्टार पान-मसाला क्यों बेच रहे हैं, क्या पान-मसाला को बेचना बहुत मुश्किल काम हो गया है कि, अकेले अजय देवगन न बेच पा रहे हैं तो शाहरुख खान को भी लगना पड़ा सेल में। बस यह न देखना पड़े कि फिल्मी दुनिया के करन-अर्जुन यानी कि सलमान और शाहरुख दोनों जोड़ी बनाकर एक ही पान-मसाला बेचें। उफ! करन-अर्जुन इतने ताकतवर थे कि, विकट विलेन को भी निपटा दिया, ऐसे परमवीरों को अब अपनी वीरता कहा दिखानी पड़ रही है पान-मसाला बेचने में। पान-मसाला बेचना आसान न है। सो एक वीर से काम न चल रहा है, दो-दो वीर लग रहे हैं। मल्टी-स्टारर पान-मसाला भी आएगा ही। पान-मसाले में 3 पीढ़ी एक साथ, यह भी किसी इश्तिहार में देखेंगे। अमिताभ बच्चन बुजुर्ग पीढ़ी के, शाहरुख खान मध्यवर्ती पीढ़ी के और रणवीर सिंह एकदम नई पीढ़ी के। 3 पीढ़ियों का मिलन दिलवाला, सब खायें मिलके पान-मसाला। एक दौर था जब अमिताभ बच्चन अकेले ही कोई बात कहते थे और लोग मान जाते थे। अब अमिताभ के साथ रणवीर सिंह का भी कन्फर्मेशन आता है कि अमिताभ सही कह रहे हैं। लोग अब आसानी से भरोसा न करते। अमिताभ बच्चन को वैसे संभल कर रहना चाहिए। इन दिनों वह एक ब्रांड की भुजिया वगैरह खूब खा रहे हैं। सेहत का ख्याल रखना चाहिए खाने पीने में। अमिताभ बच्चन बीमार, अस्पताल में, इस आशय की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर वह सेहत का ख्याल, खाने पीने का ख्याल ज्यादा रखें। हम उस डॉन वाले अमिताभ बच्चन को जानते हैं जो कहता थाकृडॉन की तलाश तो पता नहीं कितने देशों की पुलिस को है। यहां अमिताभ बच्चन ही भुजिया और पान-मसाले की तलाश मचाये हुए हैं। अमिताभ बच्चन बड़े आदमी हैं। उनके इलाज की फुल व्यवस्था है। पर कोई आम बुजुर्ग 70 के पार जाकर भी भुजिया और पान-मसाले के मामले में संयम न रखे तो समस्या हो जाएगी।

नारी कब तक बेचारगी का जीवन जीयेगी?

ललित गर्ग

हम तालिबान-अफगानिस्तान में बच्चियों एवं महिलाओं पर हो रही क्रूरता, बर्बरता शोषण की चर्चाओं में मशगूल दिखाई देते हैं लेकिन भारत में आए दिन नाबालिग बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं तक से होने वाली छेड़छाड़, बलात्कार, हिंसा की घटनाएं पर क्यों मौन साध लेते हैं? इस देश में जहां नवरात्र में कन्या पूजन किया जाता है, लोग कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोते हैं और उन्हें यथासंभव उपहार देकर देवी मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं वहीं इसी देश में बेटियों को गर्भ में ही मार दिये जाने एवं नारी अस्मिता एवं अस्तित्व को नौंचने की त्रासदी भी है। इन दोनों कृत्यों में कोई भी तो समानता नहीं बल्कि गज़ब का विरोधाभास दिखाई देता है।

दुनियाभर में महिलाओं के अस्तित्व एवं अस्मिता के लिए जागरूकता एवं आन्दोलनों के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में भी महिलाओं की स्थिति, कन्या भ्रूण हत्या की बढ़ती घटनाएं, लड़कियों की तुलना में लड़कों की बढ़ती संख्या, तलाक के बढ़ते मामले, गांवों में महिला की अशिक्षा, कुपोषण एवं शोषण, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ होने वाली बलात्कार की घटनाएं, अश्लील हरकतें और विशेष रूप से उनके खिलाफहोने वाले अपराधों पर प्रभावी चर्चा एवं कठोर निर्णयों से एक सार्थक वातावरण का निर्माण किये जाने की अपेक्षा है। क्योंकि एक टीस-सी मन में उठती है कि आखिर नारी कब तक भोग की वस्तु बनी रहेगी? उसका जीवन कब तक खतरों से घिरा रहेगा? बलात्कार, छेड़खानी, भ्रूण हत्या और दहेज की धधकती आग में वह कब तक भस्म होती रहेगी? कब तक उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को नौचा जाता रहेगा?

दरअसल, छोटी लड़कियों या महिलाओं की स्थिति अनेक मुस्लिम और अफ्रीकी देशों में दयनीय है। जबकि अनेक मुस्लिम देशों में महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान है, अफगानिस्तान-तालिबान का अपवाद है। वहां के तालिबानी शासकों ने महिलाओं को लेकर जो फरमान जारी किए हैं वो महिला-विरोधी होने के साथ दिल को दहलाने वाले हैं। नए तालिबानी फरमानों के अनुसार महिलाएं आठ वर्ष की उम्र के बाद पढ़ाई नहीं कर सकेंगी। आठ वर्ष तक वे केवल कुरान ही पढ़ेंगी। 12 वर्ष से बड़ी सभी लड़कियों और विधवाओं को जबरन तालिबानी लड़कों से निकाह करना पड़ेगा। बिना बुर्के या बिना अपने मर्द के साथ घर से बाहर निकलने वाली महिलाओं को गोली मार दी जाएगी। महिलाएं कोई नौकरी नहीं करेंगी और शासन में भागीदारी नहीं करेंगी। दूसरे मर्द से रिश्ते बनाने वाली महिलाओं को कोडों से पीटा जाएगा। महिलाएं अपने घर की बालकनी में भी बाहर नहीं झांकेंगीं। इतने कठोर, क्रूर, बर्बर और अमानवीय कानून लागू हो जाने के बावजूद अफगानिस्तान की पढ़ी-लिखी और जागरूक महिलाएं बिना डरे सड़कों पर जगह-जगह प्रदर्शन कर रही हैं। दुनिया की बड़ी शक्तियों को इन महिलाओं स्वतंत्र अस्तित्व को बचाने के लिये आगे आना चाहिए।

तमाम जागरूकता एवं सरकारी प्रयासों के भारत में भी महिलाओं की स्थिति में यथोचित बदलाव नहीं आया है। भारत में भी जब कुछ धर्म के ठेकेदार हिंसात्मक और आक्रामक तरीकों से महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं तो वे भी तालिबानी ही नजर आते हैं। विरोधाभासी बात यह है कि जो लोग नारी को संस्कारों की सीख देते हैं, उनमें से बहुत से लोग, धर्मगुरु, राजनेता एवं समाजसुधारक महिलाओं के प्रति कितनी कुत्सित मानसिकता का परिचय देते आए हैं, यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। इनके चरित्र का दोहरापन जगजाहिर हो चुका है। कोई क्या पहने, क्या खाए, किससे प्रेम करे और किससे शादी करें, सह-शिक्षा का विरोधी नजरिया- इस तरह की पुरुषवादी सोच के तहत महिलाओं को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उन पर तरह-तरह की बंदिशें एवं पहरे लगाए जा रहे हैं। वक्त बीतने के साथ सरकार को भी यह बात महसूस होने लगी है। शायद इसीलिए सरकारी योजनाओं में महिलाओं की भूमिका को अलग से चिह्नित किया जाने लगा है।

आए दिन कोई न कोई महिला अत्याचार, बलात्कार एवं शोषण की घटना सुनाई देती है जो दिल को दर्द से भर देती है और बहुत कुछ सोचने को विवश कर देती है। देश के किसी एक भाग में घटी कोई घटना सभी महिलाओं के लिए चिंता पैदा कर देती है। यूं तो महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे कानून बने हैं लेकिन अपराधियों को इनका ज़रा भी खौफ क्यों नहीं? जब देश में ऐसी कोई घटना घटित होती है तो क्यों लंबे समय तक तारीख पर तारीख लगती रहती हैं? तुरंत फैसला क्यों नहीं हो जाता इन हैवानों एवं महिला अत्याचारियों का? इन आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए क्या हमें भी कुछ मुस्लिम देशों की जैसी क्रूर सज़ा का प्रावधान करना चाहिए? एक अपराधी से कानून को क्यों हमदर्दी हो जाती हैं जो उसे अपना पक्ष रखने का अवसर सालों साल मिलता रहता है। आश्चर्य इस बात का होता है कि, इन अपराधियों के माता-पिता भी इन्हें बचाने के लिए जी जान से जुड़ जाते हैं। इस तरह कानून का संरक्षण नहीं मिलने से औरत संघर्ष के अंतिम छोर पर लड़ाई हारती रही है। लेकिन महिलाओं के प्रति एक अलग तरह का नजरिया इन सालों में बनने लगा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नारी के संपूर्ण विकास की संकल्पना को प्रस्तुत करते हुए अनेक योजनाएं लागू की है, जिनमें अब नारी सशक्तीकरण और सुरक्षा के अलावा और भी कई आयाम जोड़े गए हैं। सबसे अच्छी बात इस बार यह है कि समाज की तरक्की में महिलाओं की भूमिका को आत्मसात किया जाने लगा है।

एक कहावत है कि, ''औरत जन्मती नहीं, बना दी जाती है'' और कई कट्टर मान्यता वाले औरत को मर्द की खेती समझते हैं। इसीलिए आज की औरत को हाशिया नहीं, पूरा पृष्ठ चाहिए। पूरे पृष्ठ, जितने पुरुषों को प्राप्त हैं। पर विडम्बना है कि, उसके हिस्से के पृष्ठों को धार्मिकता के नाम पर ''धर्मग्रंथ'' एवं सामाजिकता के नाम पर ''खाप पंचायते'' घेरे बैठे हैं। पुरुष-समाज को उन आदतों, वृत्तियों, महत्वाकांक्षाओं, वासनाओं एवं कट्टरताओं को अलविदा कहना ही होगा जिनका हाथ पकड़कर वे उस ढ़लान में उतर गए जहां रफ्तार तेज है और विवेक अनियंत्रण हैं जिसका परिणाम है नारी पर हो रहे नित-नए अपराध और अत्याचार। पुरुष-समाज के प्रदूषित एवं विकृत हो चुके तौर-तरीके ही नहीं बदलने हैं बल्कि उन कारणों की जड़ों को भी उखाड़ फेंकना है जिनके कारण से बार-बार नारी को जहर के घूंट पीने एवं बेचारगी को जीने को विवश होना पड़ता है। पुरुषवर्ग नारी को देह रूप में स्वीकार करता है, लेकिन नारी को उनके सामने मस्तिष्क बनकर अपनी क्षमताओं का परिचय देना होगा, उसे अबला नहीं, सबला बनना होगा, बोझ नहीं शक्ति बनना होगा।

''यत्र पूज्यंते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता'' जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। किंतु आज हम देखते हैं कि, नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। उसे ''भोग की वस्तु'' समझकर आदमी ''अपने तरीके'' से ''इस्तेमाल'' कर रहा है, यह बेहद चिंताजनक बात है। आज अनेक शक्लों में नारी के वजूद को धुंधलाने की घटनाएं शक्ल बदल-बदल कर काले अध्याय रच रही है। देश में गैंग रेप की वारदातों में कमी भले ही आयी हो, लेकिन उन घटनाओं का रह-रह कर सामने आना त्रासद एवं दुःखद है। आवश्यकता लोगों को इस सोच तक ले जाने की है कि जो होता आया है वह भी गलत है। महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानूनों की कठोरता से अनुपालना एवं सरकारों में इच्छाशक्ति जरूरी है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरोध में लाए गए कानूनों से नारी उत्पीड़न में कितनी कमी आयी है, इसके कोई प्रभावी परिणाम देखने में नहीं आए हैं, लेकिन सामाजिक सोच में एक स्वतः परिवर्तन का वातावरण बन रहा है, यहां शुभ संकेत है।

जोबट में हुई घोषणा क्या जोबट तक सीमित, किसान का आरोप पटवारी ने पैसे लेकर भी दी फर्जी पावती

किसान ने सांसद को आवेदन दिया तो तत्काल तहसीलदार को जांच के आदेश दिए

माही की गूंज, रतलाम।

किसानों के लिए सरकार आए दिन योजनाएं बनाकर किसानों तक पहुचाती है ओर मध्यप्रदेश में कहा जाता है कि, किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है पर उन्ही की सरकार में किसान आज भी परेशान है। विगत दिनों मुख्यमंत्री जोबट दौरे पर आए थे जहां उन्होंने किसानों की जमीन के नामांतरण और सीमांकन के लिए वसुली करने वाले पटवारियों पर तत्काल कार्रवाई की बात कही थी। लेकिन घोषणावीर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा जोबट में उपचुनाव को देखते हुए सिर्फ जोबट विधानसभा के किसानों को लॉलीपॉप देने के लिए की थी, बाकी प्रदेश के किसान सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाते रहेंगे।

रतलाम जिले की बात की जाए तो किसान आज भी परेशान दिखाई दे रहे है। जिले के पिपलोदा तहसील के ग्राम चौरासी बडायला के किसान नानालाल पिता राधेश्याम धाकड़ ने जावरा एसडीएम से लेकर विधायक, कलेक्टर, उज्जैन कमिश्नर ओर मुख्यमंत्री तक शिकायत की कि, हल्का नम्बर 53 पर मेरी जमीन है जिस जमीन को मेरे नाम करवाने के लिए मानसिंह पंवार पटवारी द्वारा पैसो की मांग की गई और जमीन नाम पर करने की बात कही। पटवारी द्वारा धाकड़ को बताया गया कि, मैं यहां का पटवारी नही हु मैं इस का प्रभारी हु, कभी भी यहां से जा सकता हु ओर आपका काम करना हो तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे क्यो की में प्रभारी हु यहां का।

किसान नानालाल धाकड़ ने बताया कि, पटवारी ने पैसे की मांग की तो उन्हें बताया कि, मैं गरीब हु ओर मेरे पास इतने पैसे नही है। पटवारी साहब ने मुझे से कहा कि काम अगर करवाना है तो पैसे तो लगेंगे। पहले 30 हजार रुपए की मांग की ओर जैसे ही पिता के साइन होने बाद पीड़ित किसान से 46 हजार 6 सौ रुपयो की मांग की। जो किसान द्वारा तीन किस्तो में पटवारी साहब को दिए जाना बताया।

सांसद ने तत्काल तहसीलदार को निष्पक्ष जांच के आदेश

क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पिपलोदा जनपद भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे। जहां पर किसान द्वारा सांसद सुधीर गुप्ता को आवेदन दिया और अपनी समस्या बताई। जैसे ही सांसद ने समस्या सुनी तो तत्काल पिपलोदा तहसीलदार किरण बरबड़े को फोन कर बताया कि, इनका आवेदन मेरे पास में आया है इसकी जांच की जाए और दोषी पाए जाए तो तत्काल कार्रवाई भी करें।

क्या कहकर वसूले पटवारी ने पैसे

किसान ने बताया कि, पटवारी मांनसिह पंवार द्वारा किसान को बताया कि में इस गांव का पटवारी नही हु, इस गांव का इंचार्ज हु, पैसे तीन दिनों में ही देने पड़ेगे। जो 20 हजार रुपए आकतवासा पंचायत पर जाकर दिए, दूसरी क़िस्त 20 हजार रुपए पूनमचंद सरपंच के घर पर दिए, तीसरी क़िस्त 6 हजार 6 सौ रुपए जावरा में रौनक जूस सेन्टर पर दिए, जिसमे किसान नानालाल की पत्नी भूलीबाई व बालक जतिन ओर गांव का ही विनोद मालवीय भी पैसे देते समय साथ थे। पिड़ित किसान द्वारा इतने पैसे देने के बाद पटवारी ने किसान के हिस्से की जगह उसके नाम तो ऑनलाइन पर चढ़ा दी पर नक्शा पटवारी द्वारा अभी तक नही काटा गया। पटवारी को 46 हजार 6 सौ रुपए देने के बाद भी 17 फरवरी 2020 को बटवारा ऑनलाइन चढ़ाया गया। इसके बाद पावती बनाने के लिए पुनः 10 हजार रुपए की मांग पटवारी द्वारा की गई पर मैने 10 हजार देने से मना कर दिया, तो फर्जी पावती बनाकर गांव के चौकीदार को 22 जून 2020 को बिना तहसीलदार के सील साइन हुए ही दे दी गई।

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना पटवारी नेखुद के हस्ताक्षर कर किसान को दी पावती। तहसीलदार की सील कैसे लगी जाँच का विषय...?

जमीन नाम नहीं होने से शासकीय योजना से हुआ वंचित, कर्ज में डूबा किसान जमीन बेचने पर हुआ मजबूर

किसान ने बताया कि, पटवारी हल्का नम्बर 53 मानसिंह पंवार को पैसे देने के बाद भी मेरा काम नही हुआ तो मैं न केसीसी करा पाया न ही प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि प्राप्त कर सका। मैं इन सभी योजना का भी लाभ नही ले पाया। चौरासी बडायला के किसान नानालाल ने बताया कि, जमीन खरीदने के लिए बाजार से 2 लाख 82 हजार 5 सौ रुपए 2 प्रतिशत सैकड़ा ब्याज दर पर कर्जे से उधार लिए गए थे। जो 18 माह का ब्याज 1 लाख 18 हजार 440 रुपए व पटवारी को दिए 46 हजार 6 सौ रुपए मिलाकर 3 लाख 29 हजार 105 रुपए ओर ब्याज मिलाकर मेरे बाजार मे कर्जा 4 लाख 47 हजार 440 रुपए हो गया है। फिर मेरे द्वारा उक्त जमीन को गांव के ही विनोद मालवीय को कर्जा होने के कारण बेचना पड़ा। किसान ने बताया कि, विनोद मालवीय द्वारा पटवारी मानसिंह पंवार को फोन लगाकर बताया, पटवारी ने ही कहा कि पावती फर्जी है, उस पावती पर तो तहसीलदार के सील साइन भी नही है। बड़ी बात तो ये है कि, उसी पटवारी ने पावती बनाई और उसी पटवारी ने उसी पावती को फर्जी पावती बता दी। किसान द्वारा बताया कि, मेरी जमीन सर्वे नम्बर 664/4/2 रकबा 0.448 एक बीघा 18 बिस्वा है ओर जमीन ऑनलाइन चढ़ गई तो जमीन कैसे फ्रोड हो सकती है। पटवारी हल्का नम्बर 53 ने मेरे से इतने रुपए लेने के बाद भी मेरा काम बीच मे ही छोड़ दिया है। मेने जब 20 अगस्त 2021 को पटवारी को नक्शे के लिए फोन लगाया तो उसने बोला मैं नक्शा नही दूंगा तेरसे हो वो करले। किसान का कहना है कि, पटवारी मेरी जमीन की नप्ति करने से मनाकर रहा है ओर बोल रहा कि, मुझे 10 हजार रुपए ओर चाहिए। किसान नानालाल धाकड़ ने पटवारी को लेकर कितनी बार पिपलोदा तहसील के चक्कर लगा दिए पर जिम्मेदार कोई भी सुनने को तैयार नही। मेरे द्वारा तहसीलदार, एसडीएम जावरा, विधायक, कमिश्नर सहित मुख्यमंत्री को पटवारी की शिकायत की है पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नही है।

हाथ मिलाने के बहाने हथेली खुजा कर करते हैं रुपयों की मांग...

माही की गूंज, भानपुरा।

पत्रकारिता वर्षों से जन-जन का विश्वास, एक जुनून, जज्बा, जरूरतमंदों की आस एवं ईमानदारी का पर्याय थी। हर उस बड़े नेता व जनप्रतिनिधियों व उनके प्यादों की मनमानी को जनता के सामने लाने का जज्बा था। जो आज भी कई पत्रकारों में गर्व के साथ जिंदा है। इस पेशे को काफी सम्मान एवं इज्जत प्राप्त होती थी। लोगों को हर तरफसे निराशा मिलती थी तब जरूरतमंदों की आंखों में उम्मीद जगती थी कि हमारी, हमारे मोहल्ले की नगर की व क्षेत्र की आवाज को पत्रकार उठाएंगे और हमारा जायद काम हो जाएगा। क्षेत्र में स्थापित विभागीय कर्मचारियों, अधिकारियों की मनमानी, लेटलतीफी, न्याय प्रदान करने में कोताही की लड़ाई अपनी साफस्वच्छ कलम से पत्रकार प्रकाशित कर हमें न्याय दिलाने के मुकाम तक पहुंचाएंगे। परंतु अब हालात पूरी तरह वैसे नहीं है, पत्रकारिता की अनेक विधाओं में तरह-तरह की कपोल कल्पित पत्रकारिता जन्म ले चुकी है। अब कई तरह के पत्रकार पैदा हो चुके हैं, जो अनचाही आर्थिक प्राप्ति के लोभ एवं लोगों में अपने फर्जी पेशे का खौफपैदा कर सीधे-साधे लोगों के दोहन करने का अनचाहा अजीब धंधे में लिप्त हो चुके है। कर्मचारीयों, अधिकारियों, छोटे जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं जनसामान्य में पत्रकारिता का रोब झाड़ने वाले अनेक कुकर मुत्ते हर कहीं उग आए हैं। क्षेत्र में पत्रकारिता के नाम पर वर्षों से सम्मान पाने वाले गिने-चुने पत्रकार ही रह गए। नाम न छापने की शर्त पर अनेक बड़े-छोटे अधिकारियों ने प्रेस क्लब भानपुरा के प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को बताया कि, यहां कुछ ही ईमानदार पत्रकार रह गए हैं। वरन अवैध वसूली में लगे पत्रकारों के कारण इस पेशे में लगे हुए कई पत्रकारों के ऊपर से ही भरोसा उठ गया है।

तहसील भानपुरा के नगर गांव में गली मोहल्लों में अनेक पत्रकार कटीली झाड़ियों की तरह तेजी से पनपने चुगने व पीड़ा देने वाले पौधों की तरह उग आए हैं। ऐसे अनेकानेक फर्जी पत्रकार तरह-तरह की चैनलों के नाम पर रोब घांटकर अपने आप को पत्रकारिता के नाम पर तोपची होने का दावा करते हैं। अनचाही आर्थिक मांग करते हैं, हाथ मिलाने के बहाने अधिकारियों की हथेली पर खुजाल करते हुए हजारों रुपए देने की मांग करते हैं। मनचाहा प्रयास पूरा नहीं होने पर ब्लैक मेलिंग की धोंस देते हैं। अपने आपको सबसे अलग बताने का प्रयास करते समय अनेक राजनीतिक आकाओं के दाएं बाएं हाथ होने, जनप्रतिनिधियों के कंधे पर बैठे होने या जनप्रतिनिधियों के साथ अपने विशेष संबंध बता कर अपने आप को जिले, प्रदेश व देश के नामी-गिरामी पत्रकार होने का जज्बा भरते हैं। कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों ने इस तरह से कुकर मुत्तों की तरह गली मोहल्लों में उग आए, तथा मंदसौर जिले से, समीपस्थ तहसीलों से आकर अपनी वसूली के धंधे को चमकाने में लगे हैं। उपरोक्त पीड़ितों ने पत्रकारों से अपने आपको आए दिन परेशान किए जाने की बात प्रेस क्लब भानपुरा के पत्रकारों को बताई। इस मामले में प्रेस क्लब अध्यक्ष अनिल नाहर, हरीकृष्ण मरमट, लालचंद रुद्रवाल, करण भूटानी ने पुलिस एवं प्रशासन से मांग की है कि, इस तरह के फर्जी पत्रकारों के होने के सबूत मांगे जाए एवं फर्जी पत्रकार पाए जाने पर शासन के नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।

कृषि विज्ञान केन्द्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति बैठक सम्पन्न

माही की गूंज, शाजापुर।

कृषि विज्ञान केन्द्र पर वर्ष 2021-22 की 25 वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर दिनेश जैन के मुख्य अतिथ्य में संपन्न हुई। इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के विस्तार सेवायें निदेशक डॉ. एसएन उपाध्याय ने की। कार्यक्रम मे उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास केएस यादव, कृषि विज्ञान केन्द्र देवास के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एसके भार्गव, उपसंचालक उद्यानिकी मनीष चौहान, उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवायें डॉ. एसके श्रीवास्तव, डॉ. एमके सिंधल, कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. एसएस धाकड, डॉ. गायत्री वर्मा एवं डॉ. मुकेश सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान घनश्याम पाटीदार, जितेन्द्र पाटीदार, गोपीपुर, जुझार सिंह एंव सुनील नाहर आदि उपस्थित थे।

कार्यक्रम में केन्द्र प्रमुख डॉ. जीआर अंबावतिया द्वारा बैठक के उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला साथ ही जिले में कृषकों की आय दुगुनी करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया, जिससे कृषकों का आर्थिक विकास हो सके। इस दौरान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. एसएस धाकड़ विगत खरीफ 2021 मौसम में किए गए कार्यो एंव आगामी रबी 2021 में किए जा रहे कार्यो की

कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्री जैन द्वारा उन्नत किस्मों, जलसंरक्षण एवं संवर्धन, प्याज की उन्नत तकनीक एवं उसका मूल्य संवर्धन का प्रचार-प्रसार कर कृषकों की आय को दुगुना करने हेतु फसल विविधीकरण एवं उद्यानिकी आधारित खेती करने की बात कही। साथ ही कलेक्टर द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र शाजापुर के वैज्ञानिकों द्वारा जिले के किसानों की आय बढ़ाने हेतु किए जा रहे कार्यो की प्रशंसा की।

कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉ.एस.एन.उपाध्याय, निदेशक, विस्तार सेवायें रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर द्वारा उद्यानिको फसलों की उन्नत तकनीको एंव उन्नत कृषि यंत्रो एंव जल संरक्षण की उन्नत तकनीको का प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही कुपोषण दूर करने हेतु सोयाबीन युक्त प्रर्वधन, सुरजना रोपण एवं मूल्य संवर्धान पर ध्यान दिया जाए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. गायत्री वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में केन्द्र के रत्नेश विश्वकर्मा, हितेन्द्र इंदौरिया, कु. निकिता नंद, गंगाराम राठौर का योगदान भी सराहनीय रहा। सभी सदस्यों एंव वैज्ञानिको द्वारा जिले के कृषको एंव कृषि के सुधार हेतु बहुमूल्य सुझाव दिए गए, जिसके अनुसार किसानों से कहा गया कि, जैविक खेती को बढावा देने एंव कम पानी में होने वाली औषधीय फसलें एवं बाजार आधारित फसल चयन एंव फसलों के मुल्य संवर्धन अपनाएं। कृषि के साथ-साथ पशुपालन, डेरी, उद्यानिकी फसलें, कृषि आधारित उद्योगो पर विचार करें। फसल सुरक्षा, संतरे में पौध संरक्षण के उन्नत उपयों का प्रचार प्रसार किया जाये। फसल चक्र अपनाने एंव फसल विविधिकरण हेतु जाग्रति लाने, आलू, प्याज एवं लहसुन की उन्नत कृषि तकनीक का मैदान स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जलवायु परिर्वतन को देखते हुए फसलों एंव किस्मों में बदलाव किया जाए। फसलों की रेज्डबेड पद्धति से बुआई करें।

लोटखेड़ी से भैंसोदा मंडी तक सड़क मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील

मार्गों पर वाहन चालक जान जोखिम में डालकर वाहन चलाने को मजबूर

माही की गूंज, भानपुरा।

जरंगबली तिराहा भानपुरा से लेकर भैंसोदा मंडी तक का सड़क मार्ग एंव भैसोदा मंडी से लेदी चौराहे तक एवं यहां से कालाकोट तक के सड़क मार्गो की हालत काफी दयनीय जर्जर हो चुकी है, सड़क मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। इन मार्गों पर वाहन चलाना जान जोखिम में डालने के समान है। इन मार्गों की दयनीय स्थिति के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पूरी उदासीनता बरतने के साथ ही कुंभकरण की नींद में सोए हुए हैं। इसका खामियाजा इस मार्ग पर निकलने वाले वाहन चालकों को जान जोखिम में डालकर परेशानियां भुगतने को मजबूर होना पड़ रहा है। इन मार्गों पर सड़क पर इतने गड्ढे हो चुके हैं कहीं जगह तो गड्ढों में सड़क ही दिखाई नहीं देती है। इन दोनों मार्गों पर बड़ी संख्या में दोपहिया वाहनों चार पहिया वाहनों का प्रतिदिन आवागमन होता है। सड़क मार्ग गड्ढों में तब्दील होने से वाहन चालक वाहन को एक गड्ढे से बचाता है तो दूसरे गड्ढे से वाहन को नहीं बचा पाता है। ऐसी स्थिति में वाहनों में भी भारी टूट-फूट होना स्वाभाविक है। साथ ही गंभीर दुर्घटनाएं घटित होने की संभावनाएं भी निर्मित होती रहती है। सड़क पर गड्ढों के चलते कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। वर्तमान में इन मार्गों पर वाहन चलाना जान जोखिम में डालने से कम नहीं है।

सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि, भानपुरा नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के बुरे हाल के चलते भानपुरा नगर सहित आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भवानीमंडी का रुख करते हैं। एवं प्रतिदिन बड़ी संख्या में दो पहिया वाहनों एंव चार पहिया वाहनों से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भवानीमंडी इन्हीं जर्जर सड़क मार्गो से होकर जा रहे हैं। ऐसे में मरीजों को एवं परिजनों को गड्ढों में तब्दील हो चुके सड़क मार्ग के चलते भारी परेशानियां भोगने के साथ ही जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। इन मार्गों की दयनीय स्थिति के बावजूद भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पूरी उदासीनता बरत रहे हैं एवं क्षेत्र के जवाबदार भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे इन दोनों गड्ढा युक्त सड़क मार्ग पर कभी भी गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो सकती है।

पीडब्ल्यूडी एसडीओ कमल जैन के मोबाइल पर इस विषय को लेकर कई बार घंटी की जाने के बाद भी इनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।

पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर राहुल भार्गव ने इस संबंध में बताया कि, इन दोनों मार्गों का निर्माण होना है। दोनों रोड के रखरखाव की जवाबदारी हमारी है। बारिश के चलते हुए गड्ढों का पैच वर्क बारिश में कराना संभव नहीं था बारिश के बाद रोड के गड्ढों का पैच वर्क करवाया जाएगा।

अस्पतालों में बने ऑक्सीजन प्लांट देख-रेख के अभाव में खा रहे है धूल

माही की गूंज, मंदसौर। साहिल अगवान

जिला अस्पताल सहित गरोठ, शामगढ़, सुवासरा, सीतामऊ व नारायणगढ़ में आक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन इनको चलाने वाले आपरेटर महज दो ही हैं। इसके चलते तहसील मुख्यालयों पर बने सभी प्लांटों की अभी धूल भी साफनहीं हो पा रही है। वहीं 80 लाख रुपए में बनकर तैयार हुए जिला अस्पताल के आक्सीजन प्लांट को ठेके पर देने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल कहीं भी आक्सीजन की आवश्यकता नहीं होने से प्लांटों की देख-रेख तक नहीं हो रही है। इनके आसपास बारिश का पानी भरा हुआ है।

जिला अस्पताल के आक्सीजन प्लांट में प्रति घंटा 30 हजार लीटर आक्सीजन बन रही है। जिला अस्पताल में सेंट्रल आक्सीजन लाइन से जुड़े कुल 330 बेड हैं। 24 घंटे तक लगातार प्लांट चलाने के बाद भी सभी बेड पर आक्सीजन नहीं पहुंच रही है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार जिला अस्पताल में केवल 45-50 बेड तक ही आक्सीजन पहुंचाई जा सकती है। इससे अधिक मरीज होने पर सिलिंडर का उपयोग करना पड़ रहा है। तीसरी लहर आती है तो फिर से आक्सीजन की किल्लत सामने आ सकती है। जिला अस्पताल में दूसरे आक्सीजन प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया भी कोरोना का खतरा कम होते ही ठंडे बस्ते में चली गई है। अब याद दिलाने पर सीएमएचओ कह रहे हैं कि जिला अस्पताल परिसर में पुराने विश्रामगृह को तोड़कर आक्सीजन प्लांट बनाया जाएगा। जिले में सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ़, गरोठ और नारायणगढ़ में आक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, लेकिन कहीं भी आपरेटर नहीं होने से ये प्लांट वीरान पड़े हैं। कई दिनों तक प्लांटों के भीतर झाड़ू तक नहीं लग रही है। प्लांट के आसपास बारिश का पानी भर गया है। मशीनों पर बारिश का पानी लगने से जंग के कारण आगामी दिनों में दिक्कतें भी आएंगी और प्लांट में लगी मशीनें नियमित रूप से नहीं चलाई गईं तो जरूरत के समय प्लांट होते हुए भी आक्सीजन के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। सीएमएचओ का कहना है कि भोपाल से ही प्लांट संचालन के लिए आपरेटर नहीं भेजे गए हैं। मात्र दो आपरेटर हैं, जो जिला अस्पताल का प्लांट संभाल रहे हैं।

गरोठः आक्सीजन प्लांट के आसपास भरा गंदा पानी, सफाई भी नहीं हो रही

गरोठ में सिविल अस्पताल में 48 लाख 56 हजार रुपए में आक्सीजन प्लांट बनाया गया है। प्लांट बनकर तैयार होने तक कोरोना की लहर ठंडी हो गई थी। मरीज नहीं होने से आक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं रही तो अस्पताल प्रबंधन ने इसे लावारिस छोड़ दिया। अब न तो प्लांट में लगी मशीन चल रही है और न ही प्लांट के भीतर नियमित सफाई हो रही है। आसपास बारिश का पानी भर गया है। 48 लाख रुपए में मिली सुविधा धूल खा रही है। प्लांट को चलाने के लिए आपरेटर भी नहीं है।

बीएमओ डॉ. मनीष दानगढ़ ने बताया कि, अभी कोविड मरीज नहीं होने से आक्सीजन की जरूरत नहीं है। प्लांट चालू है व पूरी तरह देखरेख में है। देख-रेख की जिम्मेदारी डा. पंजाबी को दी है।

शामगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 48 लाख 56 हजार रुपए में आक्सीजन प्लांट बना है। 17 जुलाई को प्लांट का शुभारंभ भी हो गया है पर अभी तक मशीन चालू कर टेस्ट नहीं की है। नगर में अभी तक 95 कोरोना पाजिटिव मिले थे। इनमें से नौ की मौत हुई थी। कई लोगो की जिले व प्रदेश से बाहर के अस्पतालों में उपचार के दौरान भी मौत भी हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर में आक्सीजन की कमी से भी मौत हुई है। आक्सीजन प्लांट तैयार हुए दो माह हो गए है लेकिन अब तक बंद ही है, यहां मशीनों का चलाने के लिये आपरेटर भी नहीं है। बीएमओ डॉ. मनीष दानगढ़ ने बताया कि, प्लांट तैयार कर टेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है।

भानपुराः आक्सीजन प्लांट में विद्युत कनेक्शन ही नहीं कराया

भानपुरा शासकीय अस्पताल मे आक्सीजन प्लांट की स्वीकृति के बाद मशीने आ गई और फिट भी कर दी गई है। अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं होने के कारण प्लांट प्रारंभ करने में देरी हो रही है।

बीएमओ डॉ. वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि हमने नए ट्रांसफार्मर के लिए विद्युत कंपनी को 3 लाख 65 हजार रुपए जमा कराए हैं। एक सप्ताह में ट्रांसफार्मर लग जाएगा। विद्युत कनेक्शन के साथ ही प्लांट से कनेक्शन के लिए लाइन भी डलेगी।

जिला अस्पताल में एक और प्लांट की प्रक्रिया अब तक नहीं हुई पूरी

तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला अस्पताल में एक और नया आक्सीजन प्लांट बनाने के लिए कार्रवाई शुरू हुई थी। इसमें सांसद निधि से भी राशि स्वीकृत हुई थी लेकिन अब तक प्लांट निर्माण को लेकर कुछ भी नहीं हो पाया है। ऐसे में तीसरी लहर आती है तो जिला अस्पताल में दूसरी लहर की तरह ही आक्सीजन के लिये परेशानियां हो सकती है। आक्सीजन की उपलब्धता सिलिंडरों से करना पड़ेगी। जिला अस्पताल में स्थित प्लांट से जो आक्सीजन अभी बन रही है वह आइसीयू सहित अन्य वार्डों में पहुंच रही है।

सरकारी रिकार्ड में 135 मौत, वास्तविकता में 450 से अधिक

सरकारी रिकार्ड में कोरोना की पहली व दूसरी दोनों लहर मिलाकर कुल 135 मौते बताई जा रही है। जबकि हकीकत में लगभग 450 से अधिक मौत तो कोरोना की दूसरी लहर में ही हुई है। मुक्तिधाम के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। इसके अलावा जिला अस्पताल प्रबंधन आक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं स्वीकार रहे हैं जबकि 450 में से लगभग आधी मौतों का कारण समय पर आक्सीजन नहीं मिलना बताया जा रहा है।

न्यूज ब्रीफ

पीजी कॉलेज में होगा ओपन विशेष भर्ती अभियान का आयोजन

माही की गूंज, खरगोन। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय ओपन विशेष भर्ती अभियान का आयोजन शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में 24 सितंबर को प्रातः 10.30 बजे से सायं 5 बजे तक किया जाएगा। इस आयोजन में इपिक डॉट कॉम रीवा, अखंड पर्यावरण संस्थान, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जबलपुर एवं इनोवेटिव सॉल्यूशन भोपाल से आदि प्राइवेट कम्पनियां कुल 175 रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करेंगी।

प्राचार्य डॉ. डीडी महाजन द्वारा बताया गया कि, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी इस आयोजन का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पंजीयन निःशुल्क हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने मूल दस्तावेजों एवं उनकी छायाप्रति के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होंगे।

मुख्यमंत्री करेंगे संबोधित

माही की गूंज, खरगोन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत 27 सितंबर तक प्रथम डोज का शत-प्रतिशत टीकाकरण करने के संबंध में जिला स्तरीय, विकासखंड स्तरीय, वार्ड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्यों को 23 सितम्बर को दोपहर 2:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। समस्त कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि, जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों को एनआईसी वीडियो कांन्फ्रेंस रूम की क्षमता को देखते हुए इस रूम में आमंत्रित करें तथा शेष सदस्यों को वीसी लिंक से जुड़ने के लिए सूचित करें। मंत्री गण तथा जिलों के प्रभारी अधिकारीगण भी संबोधन को ऑनलाईन सुन सकते हैं। यह संबोधन दूरदर्शन के अलावा वेबकास्ट लिंक, फेसबुक लाइव, यू ट्यूब, ट्विटर पर देखा व सुना जा सकेगा।

खबर के बाद कलेक्टर ने बिना हस्ताक्षरित बिलों के भुगतान मामले में दिए जांच के निर्देश

जिला सीईओ ने जांच के लिए टीम की गठित, विकास खण्ड की पंचायतों की सही जांच हुई तो निकलेंगे करोड़ों के फर्जी बिल

माही की गूंज , पेटलावद (झाबुआ)।

गूंज की भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही लगातार मुहिम के बाद प्रशासन को मामले को सज्ञान लेना पड़ा। पिछले अंक में कोदली, रायपुरिया सहित विकास खण्ड की लगभग सभी पंचायतो में फर्जी बिलो के भुगतान जनपद के माध्यम में किये जाने का मामला प्रकाशित किया था। उक्त बिलो का भुगतान विगत कई वर्षो से जनपद पेटलावद द्वारा बिना किसी शासन के अधिकृत कर्मचारी और सरपंच के हस्ताक्षर के ही पोर्टल पर चढ़ाएं जा रहे थे, जिनका भुगतान आँख बंद कर किया जा रहा था। मामला गूंज द्वारा प्रकाशित करने के बाद जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा द्वारा संज्ञान में लेकर जिला सीओ सिद्धार्थ जैन को मामले की जाँच के लिए निर्देशित किया है।

मामले में जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बताया कि, उक्त मामले की जिला पंचायत सीओ को जाँच के लिए निर्देशित किया है।

जिला पंचायत सीओ का कहना है कि, जिला कलेक्टर के निर्देश पर जांच दल गठित कर दिया है जो बुधवार को संबधित पंचायतो में इस प्रकार के बिलो के भुगतान की जांच करेगी। सीओ ने बताया कि, विकास खण्ड की सभी बड़ी पंचायतो की जांच की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार रायपुरिया और कोदली पंचायत में जांच दल ने पहुँच कर मामले की जाँच की है अब जाँच दल अपनी क्या रिपोर्ट देता है ये देखना दिलचस्प होगा।

जीएसटी टेक्स चोरी और फर्जी बिल भुगतान का हो सकता है बडा खुलासा

विकास खण्ड की बड़ी पंचायतो सहित हर पंचायतो में इस प्रकार के बिलो का भुगतान हो रहा है, जिसमे किसी भी अधिकृत के हस्ताक्षर नही है और ये बिल किस मद से कैसे भुगतान हो रहे है इसका कोई नियम क़ानून नही है। ये बिल 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक के है जिसमे ज्यादातर बिलो में जीएसटी नम्बर तक नही है , न ही उस सामग्री का उल्लेख , मात्रा ,दर कुछ भी नही, तो कुछ बिल ग्राम पंचायतों में हुए निर्माण के कार्य के लिए लिये गए मटेरियल के है जिनका भुगतान पंच परमेश्वर योजना से हुआ है और ये बिल लाखो के है। हो सकता है ग्राम पंचायतो ने सामग्री खरीदी लेकिन उनके बिलो का जो भुगतान बिना किसी जबाबदार व्यक्ति के बिना हस्ताक्षर के जनपद से हुआ वो जाँच के घेरे में है ।

आनलाईन व्यवस्था पर उठे सवाल

पारदर्शिता के नाम पर सरकार ने भुगतान के लिए जो आनलाईन व्यवस्था की है वो अब सवालों के घेरे में आ गई है , आखिर बिना हस्ताक्षर वाले बिल कैसे पोर्टल पर जनरेट हो रहे है और भुगतान के समय उनको कमियां होने के बाद भी क्यो नही रोका जा रहा है ? ये बड़ा सवाल है और सरकार की मंशा पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।

भगवान भरोसे जनपद पंचायत पेटलावद
बिलो के भुगतान में खुलेआम हो रहा फर्जीवाड़ा, बिना सचिव, रोजगार सहायक के हस्ताक्षर के जनरेट हो रहे बिलो का किया जा रहा भुगतान

अतिक्रमण का अंबार

माही की गूंज,थांदला।

बस स्टैंड प्रवेश के दोनों छोर पर दो पहिया,चार पहिया वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है जिसके चलते बसों के आवागमन में दिक्कत आती है तो दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है बस स्टैंड के सुतरेटि चौराहा से एमजी मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर भी दुकानदारों द्वारा अनाप सनाप अतिक्रमण करने से आए दिन यहां जाम की स्थित लगी रहती है। एमजी रोड वाली सड़क को ऋतुराज कॉलोनी नवापाड़ा जाने वाली सड़क तेजाजी मंदिर के सामने की ओर जलजमाव हमेशा बना रहता है सड़क के दोनों और हमेशा पानी भरा रहता है इस जलजमाव में विगत तेजा दशमी पर्व के दिन भी कुत्ता मरा पड़ा था यह कौन लोग डेंगू जैसी बीमारी से जूझ रहा है वही इस जलजमाव से इसमें कुत्ते मरे हुए पड़े जिन से बीमारियों को भाई और अधिक बढ़ता जा रहा है और मच्छरों का मच्छर भी पनप रहा है ऐसी स्थिति में लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है नगर परिषद इस और कोई ध्यान नहीं दे रही जिससे डेंगू का प्रकोप और अधिक बढ़ेगा पहले भी नगर में डेंगू से एक मासूम बच्चे की मौत हो चुकी है और यह मार्ग संस्कार स्कूल में जाने वाले बच्चे भी इसी मार्ग से निकलते आते जाते हैं यदि ऐसा जलजमाव हमेशा बना रहा या भरा पड़ा रहा तो बीमारी को साथ में दुर्घटना का भय बना रहता है ब स्टैंड के एक ओर टेम्पो,अवैध संचालित होने वाली जीपों की वजह से कई बसों को पेटलावद रोड पर खड़ा करना पड़ता है जिससे इस रोड पर भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

रात में रहता अंधेरा

नगर के बस स्टैंड से प्रति दिन लगभग 75 बसों का आवागमन है जो जिले सहित महानगर इंदौर पड़ोसी जिलों सहित राजस्थान गुजरात की ओर आवागमन करती जिनमे 2 से 3 हजार यात्री प्रतिदिन यहां से यात्रा करते है किंतु पर्याप्त विद्युत व्यवस्था न होने के चलते शाम ढलते ही बेस स्टैंड पर न पहुच कर यत्र तत्र सावरिया उतरती चढ़ाती है। ब स्टैंड पर पेयजल की व्यवस्था न होने से यात्रियों को कंठ तर करने यहाँ वहां भटकना पड़ता है।

सुरक्षा के नही इंतजाम

जिला मुख्यालय के बाद सबसे बड़े बस स्टैंड पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नही जिसके चलते स्टैंड क्षेत्र में अपराधी ओर आवारा प्रवृत्ति के लोगो का जमावड़ा रहता है। सुरक्षा के अभाव में विशेष कर महिलाओ,युवतियों तथा छात्राओं को यात्रा करने में हमेशा भय बना रहता है नगर परिषद ने नगर के अन्य क्षेत्रों में 47 सीसी टीवी कैमरे लगवाने किन्तु जिस स्टैंड से हजारों यात्री यात्रा करते वहां सीसी टीवी कैमरा लगाना उचित नही समझा।

स्वच्छता पखवाड़े के 9 वें दिन नर्मदा रिट्रीट होटल में स्वच्छता अभियान

माही की गूंज, खरगोन।

जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के 9वें दिन पर्यटन विभाग की इकाईयों में स्वच्छता अभियान गतिविधि के तहत् महेश्वर स्थित नर्मदा रिसोर्ट में अभियान चलाया गया। निर्देशानुसार होटल के प्रवेश द्वारों, परिसर एवं स्टोर रूम में स्टॉफएवं अन्य कर्मचारियों द्वारा सफाई की गई।

रिसोर्ट के प्रबंधक गोविन्दा ईरोधा ने बताया कि, कहावत है जैसा खाए अन्न-वैसा रहे मन। मन-तन एवं भोजन स्वच्छ हो तो व्यक्ति जरूर स्वस्थ्य होगा। नायब तहसीलदार अनिल मौर्या द्वारा समस्त स्टॉफ को शपथ दिलायी गई कि वे इकाई में स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे। अपने कार्यस्थल को स्वच्छ रखेंगे। स्वयं श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ भी करेंगे। रिसोर्ट में गंदगी न करेंगे ना करने देंगे। रिसोर्ट के शौचालय को साफ स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे। साथ ही पान-गुटखा-तंबाखु के सेवन को हतोत्साहित करेंगे।

जिला नोडल नीरज अमझेरे ने बताया कि, पर्यटन विभाग की पंच लाईन है अतिथि देवो भवः अर्थात् अतिथि देवता समान है। हमें अतिथि को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना आवश्यक है। पर्यटक जब भी पर्यटन स्थलों या पर्यटन होटल, रिसोर्ट में जाता है तो सबसे पहले वहाँ की स्वच्छता का अवलोकन करता है। स्वच्छ व सुंदर वातावरण की अनुभूतियाँ लेकर वह अपने गंतव्य की ओर लौटता है। हमें आने वाले समस्त पर्यटकों को हमारा स्वच्छ व स्वस्थ्य आतिथ्य उपलब्ध कराना आवश्यक है।

गतिविधि में नायब तहसीलदार के साथ प्रबंधक नर्मदा रिसोर्ट, विजय पटेल, नवल किशोर, मोहन सोनी, बृजेश मिश्रा, सूर्यप्रकाश रघुवंशी, कुलदीप, राजा, महेन्द्र, पिंटु, उपेन्द्र, बावी, सतीश खरे, गोपाल, कुंदन, सूर्या आदि कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वतंत्रता के 75 वर्ष का स्मरणोत्सव के तहत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत फ्रीडम रन का आयोजन

माही की गूंज, झाबुआ।

25 सितम्बर 2021 को स्वतंत्रता के 75 वर्ष का स्मरणोत्सव के तहत आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत फ्रीडम रन का आयोजन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केन्द्र जिला झाबुआ द्वारा दिनांक 25 सितम्बर शनिवार को प्रातः 7.30 पर झाबुआ बस स्टैण्ड से प्रारम्भ होकर पीजी कॉलेज झाबुआ के ग्राउण्ड पर सम्पन्न होगी। सभी से अनुरोध है कि उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करें।

कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं होने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

माही की गूंज, झाबुआ। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में श्यामा प्रसाद रूरबन मिशन योजना अंतर्गत संकूल ग्वाली एवं मोहनकोट की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित थी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिद्धार्थ जैन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर अनिल भाना, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सीओ जनपद पंचायत मेघनगर, पेटलावद, प्रभारी अधिकारी जेल इंडिया लिमिटेड, प्रभारी अधिकारी उमान, अनुभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मेघनगर एवं पेटलावद एवं क्लस्टर ग्राम पंचायत सचिव एवं युवा सलाहकार रूरबन मिशन पेटलावद एंव मेघनगर उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर मिश्रा के द्वारा रूरबन मिशन के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यो की पीपीटी के माध्यम से समीक्षा की एवं निर्देश दिए की इन क्षेत्रों में जो भी निर्माण कार्य लिए गए है। उन्हें तत्काल पूर्ण किए जाए। यदि आज दिनांक तक अपूर्ण कार्य है तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस क्षेत्र में यदि अवैद्ध उत्खन्न पाया जाता है। तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। बैठक में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव एवं पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

गूंज असर

स्टेट हाइवे पर बेशकीमती भूमि पर अतिक्रमण करने वालो को राजस्व विभाग ने थमाया नोटिस

अतिक्रमण हटाने के लिए तहसील न्यायालय से जारी हुए आदेश

माही की गूंज , पेटलावद।

स्टेट हाइवे थांदला-बदनावर मार्ग पर ग्राम पंचायत करडावद में मॉडल स्कूल के निचे वाली शासकीय भूमि सर्वे नम्बर 2985 पर रातो-रात ग्राम पंचायत करडावद के लोगो द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। मामला गूंज ने पिछले अंक में प्रमुखता से प्रकिशत किया था जिसके बाद राजस्व विभाग पेटलावद ने हरकत में आते हुए मौके पर अतिक्रमण करने वाले 06 लोगो को नोटिस जारी कर 21 सितंबर तक अतिक्रमण हटाने को कहा था ओर अतिक्रमण नही हटाने की स्थिति में कानूनी कार्यवाही करने का नोटिस दिया था लेकिन अतिक्रमणकार्ताओ ने वकील पत्र लगा कर मामला अटकाने की कोशिश की लेकिन अतिक्रमण हटाने की प्रशासन द्वारा दी गई तिथि तक अतिक्रमण नही पर तहसील न्यायलय द्वारा 22 सितंबर को अतिक्रमण मौके से हटाने के लिए 09 सदस्यों की टीम का गठन कर अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी कर दिये।

मौके से हटाया अतिक्रमण

गूँज द्वारा स्टेट हाइवे पर अतिक्रमण की गई करोड़ो की बेशकीमती जमीन का मामला प्रमुखता से उठाया था , उक्त मामले में लगातार अधिकारी अतिक्रमण को लेकर पसपोष में थे ओर लगातार सेटिंग की खबरे आ रही थी लेकिन भारी दबाव के बीच आज मौके पर से कब्जाधारीयो को हटा दिया ।

भूमाफियाओ की नजर , प्रशासन ने कब्जे में ली भूमि

शासकीय सर्वे नम्बर 2985 की भूमि स्टेट हाइवे से लगी हुई है जिस पर भूमाफियाओ को नजर कब से जमी हुई थी लेकिन पहले उक्त भूमि पर पेट्रोल पंप मालिक द्वारा अपनी होने का दावा किया जा रहा था जिसके सीमांकन के बाद शासकीय मद की भूमि सामने आई , अचानक कुछ लोगों ने कब्जा कर 2018 में उक्त भूमि पर कब्जा होने का दावा कर दिया जिसे फिलहाल हटा दिया है और खम्बे लगा कर कब्जा प्रशासन ने कर लिया है लेकिन भूमाफिया उक्त भूमि को कब्जाने के हर कोशिश करेंगे ये तय है ।

पट्टे की होनी चाहिये जॉच

ये पहली सरकारी भूमि नही जिसे राजस्व विभाग ने ठिकाने लगा दिया यहां भी कुछ ऐसा ही खेल पूर्व पटवारी और तहसीलदार द्वारा खेला गया था जिन्होंने ने बिना किसी ठोस दस्तावेजों के उक्त भूमि पर पट्टे जारी कर दिए और ये पट्टे शासकीय रेकॉर्ड में दर्ज तक नही है जिससे साफहोता है कि या तो जो पट्टे बताये जा रहे है वो फर्जी है या फिर जिन्होंने पट्टे जारी किए उन्होंने साठगांठ कर ऊपर ऊपर पट्टे जारी कर दिए जिसको आधार बना कर लोग सरकारी भूमि पर कब्जा कर सके , संभव है करोड़ो की भूमि के लिए लाखो की लेन देंन हुई होगी , क्या जिला कलेक्टर शोमेश मिश्रा और आई एस एसडीएम शिशिर गेमावत इस पट्टे के खेल को उजागर करेंगे या पेट घुटने की तरफमुड़ेगा की तर्ज को मामले को फिलहाल रफ़ दफ़ कर दिया जाएगा।

संबल हितग्राहियों के खाते में डालेगी राशि

माही की गूंज, खरगोन।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 सितंबर को झिरन्या में प्रस्तावित कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) हितग्राहियों को सीधे उनके खातों में राशि अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री चौहान जिले के कुल 871 हितग्राहियों को 19 करोड़ 13 लाख रूपए की संबल राशि प्रदान करेंगे।

श्रम अधिकारी शैलेन्द्रसिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि, इसमें भीकनगांव जनपद के 178 और नगर परिषद भीकनगांव के 30 इस तरह भीकनगांव के कुल 208 हितग्राहियों को 466 लाख रूपए की राशि और झिरन्या जनपद के 141 हितग्राहियों को 306 लाख रूपए का संबल प्रदान करेंगे। इसके अलावा बड़वाह जनपद के 220 हितग्राहियों को 487 लाख रूपए व नपा बड़वा हके 27 हितग्राहियों को 56 लाख तथा नपा सनावद के 23 हितग्राहियों को 52 लाख रूपये की राशि आंतरित की जाएगी। जबकि 252 हितग्राही जिले के अन्य नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राही शामिल है।

ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर मिश्रा

माही की गूंज, झाबुआ। जिला अस्पताल के समीप नव निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने रात्री को कलेक्टर सोमेश मिश्रा पहुंचे। यहां पर चाईल्ड आईसीयू रूम निर्माण का भी अवलोकन किया। यह ऑक्सीजन प्लांट तत्काल प्रारम्भ होना है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.पी.एस.ठाकुर , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एल.एन.गर्ग, सविल सर्जन डॉ. बी.एस.बघेल, तहसीलदार झाबुआ आशिष राठौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राजाराम खन्ना आदि उपस्थित थे। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक निर्देश दिए।

पीला मोजेक से जिले में फसल प्रभावित हो रही, सरकार नहीं ले रही सुध- विधायक पटेल

दिशाहीन हो गई सरकार, बिजली के ज्यादा राशि के बील भेजकर किया जा रहा किसानों का शोषण

माही की गूंज, अलीराजपुर।

कोरोना महामारी के संकट दौर में जिले के किसानों को लगातार दूसरे वर्ष प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड रहा है, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पीला मोजेक नामक बिमारी से किसानों की उडद और सोयाबीन की फसल बर्बाद हो रही है। लेकिन प्रदेश की दिशाहीन सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। उल्टे ज्यादा राशि के बिजली के बील भेजकर किसानों का शोषण करने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड रही है। जो किसान ज्यादा राशि के बिजली के बील नहीं भर पा रहे है उनके बिजली कनेक्शन विद्युत कंपनी द्वारा काटे जा रहे है। वहीं क्षेत्र में किसानों को जरूरत के समय पर्याप्त खाद नहीं मिल पाता है। वे खाद की निजी दुकानों पर घंटों इंतजार कर महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर होते है। अभी तक जिले का कोई अधिकारी पीला मौजेक से प्रभावित फसल का मुआयना करने भी किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा है। यदि 15 दिन में किसानों की फसलों का मुआयना कर मुआवजा प्रकरण नहीं बनाएं गए तो कांग्रेस पार्टी द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। उक्त बात विधायक मुकेश पटेल ने प्रेस विज्ञप्ति में कही।

विधायक पटेल ने बताया कि, विधानसभा क्षेत्र के सोण्डवा विकास खंड के ग्राम डाबडी के किसान करमा वेस्ता, इडा मालसिंह व कदम ने सूचित किया है कि, हमारी फसल पीला मोजेक बिमारी से बर्बाद हो रही है। इसी प्रकार आलीराजपुर विकासखंड के ग्राम बडदला के किसान भुरू पिता इन्दरसिंह ने बताया कि, मेरी उडद की फसल भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। वहीं कटठीवाडा विकासखंड के ग्राम बोकडिया के दौलत पिता भावसिंह और माधु पिता वेलसिंह की फसल भी खराब हो रही है। इस प्रकार जिले और आलीराजपुर विधानसभा के विभिन्न गांवों में किसानों को पीला मोजेक से मुश्किलों का सामना करना पड रहा है।

किसानों पर पड रही चौतरफा मार, सरकार बिजली बील की वसूली में लगी सरकार

विधायक पटेल ने बताया कि, कोरोना महामारी के इस संकटकाल में किसानों को चौतरफा मार का सामना करना पड रहा है। येलो मोजेक के रूप में किसान प्राकृतिक मार झेलने को मजबूर है। वहीं इस दिशाहीन सरकार द्वारा किसानो से बेतहाशा बिजली के बिलो की वसूली की जा रही है और उन्हें समय पर खाद भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल सहित बढती महंगाई के कारण भी किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। कोरोनो काल में किसानों के पास रूपया नहीं बचा है तो वो बिजली के बील कैसे भरेंगे और महंगे दाम पर बाजार से खाद कैसे खरीदेंगे। सरकार किसानों की मदद करने की बजाय उनका शोषण करने में लगी हुई है।

हर उपभोक्ता का पूरा बिजली बील माफकरे सरकार, किसानों को मुआवजा दे सरकार

विधायक पटेल ने सरकार से मांग की है कि, संकट की इस घडी में किसानों और आम उपभोक्ताओं का पिछले छह महीने और आगामी चार महीनों का संपूर्ण बिजली बील सरकार माफकरे। जिससे किसानों व हर वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। वहीं पीला मोजेक से प्रभावित हर किसान को उसकी फसल का मुआवजा दिया जाए। यदि सरकार ने किसानों के हित में फैसला नहीं लिया तो कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्टोरेट का घेराव कर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

एसपी सिंह पुलिसींग के अलग अंदाज में नजर आए

ग्रामीणों से चर्चा की, बच्चों-युवाओं के साथ खेल गतिविधियों में सहभाग किया

माही की गूंज, अलीराजपुर।

एसपी मनोज कुमार सिंह ने सोल पुलिसींग की विशेष पहल जिले में प्रारंभ की है। उन्होंने बखतगढ थाना क्षेत्र के ग्राम मथवाड में पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याएं जानी। शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में ग्रामीणों, युवाओं को जानकारी देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के प्रति सम्मान तथा शासन की विभिन्न योजनाओं से जुडकर ग्रामीणों को आगे बढने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए आमजन के बीच पुलिस के प्रति डर के भाव को कम करने के प्रयासों को बल दिया। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए पुलिस से डरने के बजाए मददगार के रूप में देखने पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी चर्चा करते हुए बच्चों के साथ खेलकर उनके बीच पुलिस के प्रति भय अथवा डर को कम करने तथा सोल पुलिसींग के एक अलग अंदाज को सामने रखा। इस दौरान ग्रामीणजन एवं बच्चें भी पुलिस अधीक्षक श्री सिंह को सहज रूप में देखकर काफी खुश नजर आए और ग्रामीणों तथा बच्चों ने पुलिस अधीक्षक श्री सिंह के साथ खुलकर तथा सहज रूप से चर्चा की।

पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया, जिले में पुलिस और आमजन के बीच सोल पुलिसींग के माध्यम से सकारात्मक वातावरण तैयार करने के प्रयासों को बल दिया जाएगा।

सांसद ने राज्यसभा मंत्री सिंधिया से मुलाकात कर सौंपा मांग पत्र

माही की गूंज, अलीराजपुर।

केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करते हुए रतलाम-झाबुआ-अलीराजपुर क्षेत्र सांसद गुमान सिंह डामोर ने संसदीय क्षेत्र के रतलाम नगर में हवाई अड्डे की मांग की। उन्होंने बताया, रतलाम से 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे निकल रहा है, पश्चिम रेल्वे मंडल का कार्यालय भी है, टैक्सटाइल पार्क व औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो रहा है। अतः संपूर्ण मालवा क्षेत्र के विकास के लिए रतलाम में हवाई अड्डा अति आवश्यक है। झाबुआ जिले में झाबुआ हवाई पट्टी का विस्तारीकरण, सुढ़ीकरण, बाउंड्री वल फेंसिंग भी आवश्यक है। सांसद डामोर ने अलीराजपुर जिले में हवाई पट्टी निर्माण की स्वीति का अनुरोध किया। अलीराजपुर जिले में चंद्रशेखर आजाद नगर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म स्थली है, माँ नर्मदा के किनारे होने से नर्मदा परिक्रमा मार्ग से गुजरता है, अतः अलीराजपुर के चंद्रशेखर आजाद नगर में हवाई पट्टी की स्वीकृति प्रदान करने की श्री सिंधिया से मांग की।

पोस्टमार्टम रूम हेतु दिया ज्ञापन

माही की गूंज ,थांदला।

राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला बाल विकास आयोग के प्रदेश प्रभारी कीर्तिश जैन, कार्यवाहक प्रदेशाध्यक्ष प्रदेश महासचिव मोहनलाल पाटिदार, अटल सामाजिक सेवा संस्थान मध्यप्रदेश के संचालक राजू धानक जिलाध्यक्ष तहसील अध्यक्ष गोपाल चोयल, कालू भाई ठंडाई वालें, आदि ने झाबुआ जिला मुख्यालय पहुँचकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी जे पी एस ठाकुर से जिलें में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर चर्चा की। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि, पेटलावद व थांदला के सिविल अस्पताल में स्टॉफकी कमी है जिसे दुरुस्त किया जाना बहुत आवश्यक है। थांदला में तो शिशु रोग विशेषज्ञ के चले जाने से हालात बहुत खराब हो गये है, ऐसे में जिला मुख्यालय पर 4 शिशुरोग विशेषज्ञ में से एक को थांदला किया जाए। वही नगर के आसपास बड़े घाट होने से आए दिन दुर्घटना होती रहती है जिसके चलते एक सर्जन व हड्डिरोग विशेषज्ञ की भी आवश्यकता है। जिस पर त्वरित निर्णय लेते हुए ठाकुर ने सप्ताह में 3 दिन एक आर्थो सर्जन को थांदला भेजने की बात कही। संस्था पदाधिकारियों ने ज़िलें में थांदला, मेघनगर, पेटलावद जैसी तहसील स्तरीय अनेक बड़े स्थानों पर बने जीर्ण-शीर्ण पोस्टमार्टम रूम के दुरस्त करने की मांग की वही रायपुरिया जैसी पंचायत स्तर पर अति आवश्यक स्थानों पर पोस्टमार्टम रूम के बनाने की मांग रखते हुए एक ज्ञापन सौंपा। सुमित्रा मेड़ा, गोपाल विश्वकर्मा, राजू मेड़ा, झाबुआ जिलाध्यक्ष रेखा भूरिया, गायत्री सेन, आदि भी अंचल में वैक्सीनेशन अभियान पर कार्य कर रही है। सीएमएचओ डॉ ठाकुर ने संस्था के प्रयासों की सरहना करते हुए सभी को धन्यवाद दिया वही संगठन की मांग को जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ राहुल गणावा सहयोगी स्टाफव संगठन के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

चंद्रशेखर आजाद नगर में नवागत थाना प्रभारी ने किया पदभार ग्रहण

माही की गूंज, अलीराजपुर। चंद्रशेखर आजाद नगर में नवागत थाना प्रभारी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया गया है। जिसको देखते हुए समाजसेवी नवाबी कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा नवागत थाना प्रभारी का पुष्पमाला से स्वागत किया गया। साथ ही आशा और उम्मीद की कि, आजाद नगर में बढ़ते अपराध नगर में बढ़ती चोरियों पर नवागत थाना प्रभारी के द्वारा अंकुश लगाया जाएगा।

थाना प्रभारी ने कहा, शांति व्यवस्था बरकरार रखना मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ पुलिस के प्रति लोगों के विश्वास को कायम रखने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर नवाबी कमेटी सदर अखलाक नवाबी व मुस्लिम समाज से अब्दुल्ला पठान आरिफ नवाबी वह मुस्लिम समाज युवा अरशद खान पत्रकार उपस्थित रहे।

कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण आवश्यक- प्रभारी कलेक्टर

माही की गूंज, अलीराजपुर।

प्रभारी कलेक्टर श्रीमती संस्कृति जैन ने समस्त जिलेवासियों से आह्वान किया है कि, कोरोना से बचाव का टीका जिस भी व्यक्ति ने नहीं लगवाया है वह टीकाकरण जरूर कराए। टीका पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने टीकाकरण का पहला डोज लगवा चुके ऐसे व्यक्ति जो द्वितीय डोज लगवाने के लिए निर्धारित समयावधि प्राप्त कर चुके है। वे टीके का द्वितीय डोज जरूर लगवाएं। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि, कोरोना से बचाव हेतु टीकाकरण आवश्यक है। अतः टीकाकरण जरूर कराए।

भोज मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि बढ़ाई

माही की गूंज, थांदला।

भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल के अध्ययन केंद्र क्रमांक 0205 शासकीय महाविद्यालय थांदला में प्रवेश लेने हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है। भोज मुक्त विश्वविद्यालय शासकीय महाविद्यालय थांदला के प्रभारी डॉक्टर पीटर डोडियार ने बताया कि, जो परीक्षार्थी भोज मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत यदि बीएए, बी.कॉम, एबीएससी प्रथम वर्ष, एमए अर्थशास्त्र, एएमए समाजशास्त्र, एमकॉम वित्तीय प्रबंधन, एम एस डब्ल्यू ,बीबीए, एमबीए, एएम, बी ए, एम एमए डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशनए डिप्लोमा इन मैनेजमेंट तथा सर्टिफिक्रेट इन रूरल डेवलपमेंट के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है।

दाऊदी बोहरा जमात में शत-प्रतिशत हुआ टीकाकरण, अन्य समाजों को मिलेगी प्रेरणा

माही की गूंज, आम्बुआ ।

कोरोना महामारी को हराने के लिए शासन प्रशासन स्तर से लेकर आम नागरिक भी प्रयासरत है, चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में लगभग हर वर्ग का सहयोग मिलना जरूरी माना जा रहा है। आम्बुआ में बोहरा जमात इस अभियान में अग्रणीय बना हुआ है, जमात में 18 वर्ष से ऊपर के लगभग सभी को प्रथम तथा दूसरा डोस लग चुका है।

गूंज संवाददाता को जमात के हुसैन नजमी में बताया कि, विगत 2 वर्ष से पूरे देश के लोग जिस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं शासन-प्रशासन जी तोर प्रयास कर रहा है। ऐसे में हम सभी समाज के नागरिकों को अपना सहयोग देना चाहिए, हमारे दाऊदी बौहरा जमात के धर्मगुरु डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहेब के निर्देशानुसार समाज के वह सभी महिला-पुरुष जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उन सभी को शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना की वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। आम्बुआ स्थित दाऊदी बौहरा जमात के 18 वर्ष से ऊपर के सभी महिला-पुरुषों ने पहला तथा दूसरा टीका अपनी बारी आने पर लगवा लिया है। जमात में 100 प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है, जिन 18 वर्ष वाले युवाओं को प्रथम टीका लग गया है वे समय सीमा के अंतर्गत दूसरा टीका भी लगवा रहे हैं।

भू-अभिलेख (रिकार्ड) शुद्धिकरण पखवाड़ा

माही की गूजं, झाबुआ। भू-अभिलेख (रिकार्ड) शुद्धिकरण मनाये जाने एवं इस पखवाड़े में अधिकतम भू-अभिलेख (रिकार्ड) का शुद्धिकरण हेतु निर्देश जारी किए गए है। जिसमें मध्यप्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 1 नवंबर 2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 15 नवंबर 2021 तक भू-अभिलेख (रिकार्ड) शुद्धिकरण पखवाड़ा मनाया जाएगा। यह अभियान तत्काल चलाए जाने के निर्देश दिए गए है। इस पखवाड़े में अधिक से अधिक संख्या में भू-अभिलेख शुद्धिकरण हेतु प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही की जावे और प्रकरणों का निराकरण इस पखवाडा अवधि में किया जावे।

'संभाग स्तर प्रतिभाओं ने जिले का बढ़ाया गौरव

माही की गूंज, थांदला। प्रतिभा के प्रदर्शन का अगर अवसर प्राप्त होता है और प्रतिभा निखारने के लिए उचित मंच मिलता है तो आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के नवयुवा वर्ग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हर स्तर पर कर, इस जिले का नाम रोशन कर सकते है। वैसे जिले के अनेक छात्र-.छात्राओ, खिलाड़ियो, महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता व खेलो का प्रदर्शन जिला, संभाग, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर तक कर इस जिले का नाम रोशन किया है।

वर्तमान में संभागीय स्तर बॉडीबिलिंडग मिस्टर चेम्पियन शिविर 2021 का आयोजन मध्यप्रदेश बाडीबिलिंडग एशियन इंदौर द्वारा रखा गया था, जिसमे मध्यप्रदेश के अनेक बॉडीबिलिंडग चैम्पियनो ने भाग लिया । उक्त आयोजन में थांदला क्षेत्र के तीन युवाओं को भी अपनी किस्मत आजमाने का अवसर प्राप्त हुआ ओर तीनो युवा ने नम्बर वन का स्थान प्राप्त कर एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया ।

'इन युवाओं ने लिया भाग'

संभाग स्तरीय इस आयोजन में थांदला के जय जैन व चिराग बारिया तथा मेघनगर के तुषार बसोड़ ने शामिल होकर दमखम के साथ अपना वर्चस्व दिखाया तथा विजय प्राप्त की।

डेंगू से हुई मासूम की मौत, नगर मे पसरा पड़ा है गंदगी का अंबार

माही की गूंज, थांदला।

प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी कर रहा है, वही दूसरी ओर डेगु ने क्षेत्र मे अपने पैर पसारना शुरू कर दिए है। क्षेत्र मे डेंगु का कहर प्रतिदिन बढता जा रहा है। प्रशासन की डेंगु से लडने के प्रयास नाकाम सिद्व हो रहे है बडे बर्जुगो के साथ डेगु की चपेट मे बच्चे भी बिमारी का शिकार हो रहे है। नगर के गांधी चौक निवासी शहादत खान के 11 वर्षीय पुत्र शारीन खान की डेंगु से मौत भी हो गई है। शहादत खान ने बताया कि, बच्चे को बुखार आने पर खुन की जांच करवाई डेंगु की पुष्टि होने पर सिविल अस्पताल मे भर्ती करवाया था। दो दिन ठीक रहने के बाद तीसरे दिन तेज बुखार आया सिविल अस्पताल के डाक्टरो ने काफी प्रयास किये, लेकिन स्थिति बिगडने पर जिला चिकित्सालय रेफर किया, लेकिन जिला अस्पताल के गेट पर ही बच्चे ने दम तोड दिया।

गौरतलब है कि, हास्पिटल मे पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कमलेश परस्ते के स्थानान्तरण के बाद शिशु रोग विशेषज्ञ की सख्त आवश्यकता बनी हूई है। सिविल हास्पिटल की ओपीडी भी 400 के करीब प्रतिदिन की पहुच चुकी है, जिसमे डेगु व वायरल बुखार के मरीज ज्यादा आ रहे है।

डॉक्टर मनीष दुबे ने बताया कि, क्षेत्र मे हास्पिटल मे मरीजो की संख्या लगातार बढ रही है, मौसमी बीमारियों के मरीजो की संख्या मे तेजी से इजाफा हुआ है। निजी पैथालाजी संचालको के अनुसार प्रतिदिन 5 से 6 मरीज डेंगु के आ रहे है। डेगु व वायरल से निपटने के प्रशासन के प्रयासो के बारे मे बीएमओ अनिल राठौर ने बताया कि, डेंगु प्रभावित क्षेत्रो मे सर्वे टीम को सक्रिय कर आसपास के पूरे क्षेत्र मे नमूने लिए जा रहे। जलभराव व पानी इकटठा होने वाले स्थानो पर लार्वा की जांच कर फागिंग भी करवा रहे है।

डेगु की बिमारी का शिकार हुआ मासुम शारीन खान की हुई मौत।

मलेरिया वर्कस, एएनएम, आशा व आंगनवाडी कार्यकर्ता का दल बनाकर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र मे लोगो को समझाईश दी जा रही है। नगर मे भी कई ऐसे स्थान है जहॉ जलभराव हमेशा बना रहता है, ऐसे स्थानो पर डेंगु के लार्वा पनपने की पूरी संभावना है।

8, डेंगु की बिमारी का कहर के बावजुद नगर गंदगी व गंदे पानी से भरे गड्ढे से पसरा हुआ है ।

नगर परिषद सीएमओ भारतसिंह टांक ने बताया कि, डेंगु व मौसमी बीमारियों से लोगो को सर्तक करने के लिये नगर मे मुनादी करवाई गई है। अपने आसपास पानी इकट्ठा नही होने देने की अपील के साथ ही नगर में लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है।

डेंगू, चिकनगुनिया ने दी दस्तक, मच्छरों की भरमार दवा का छिड़काव नहीं

माही की गूंज, आम्बुआ।

बरसात का मौसम को मौसमी बीमारियों का जनक भी कहा जाता है, इस मौसम में बीमारियां अपने पैर पसारती है। विशेषकर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया तथा विगत वर्षो से चली आ रही कोरोना बीमारी तथा सर्दी, जुखाम, बुखार आदि है। इस मौसम में लोगों को सचेत रहने के साथ-साथ प्रशासन को भी सतर्क रहना जरूरी है, मगर आम्बुआ क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं दिए जाने के कारण बीमारियां पैर पसार ने लगी है। शासकीय तथा निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर लग रही भीड़ इसकी गवाह है।

आम्बुआ में दो डेंगू मरीजों का पता चला है। विगत वर्ष से लोग कोरोना महामारी से ग्रस्त रहे हैं अभी कुछ राहत मिली ही थी कि, क्षेत्र में वर्षा जनित बीमारियों ने पांव पसारना प्रारंभ कर दिया है। क्षेत्र में लंबे समय से मलेरिया से बचाव हेतु मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव नही हुआ है और न ही क्षेत्र में धुआं करने वाली मशीन का उपयोग हुआ। यही कारण है वर्षा के इस मौसम में अब मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों की संभावना बढ़ने लगी है। आम्बुआ पंचायत प्रांगण के समीप विगत सप्ताह एक युवक को डेंगू होने से दाहोद इलाज कराया गया। 21 सितंबर को एक अन्य लड़का बीमार होने पर उसे भी दाहोद ले जाया गया, जहां पर उसे डेंगू होने की पुष्टि के बाद भर्ती कराना पड़ा है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बीमारों की संख्या बढ़ सकती है मगर बीमार सरकारी अस्पताल में कोरोना की जांच के डर से नहीं जाकर निजी चिकित्सकों (अलीराजपुर, जोबट तथा दाहोद गुजरात) पास जाकर इलाज करा रहे हैं। जिस कारण शासकीय अस्पतालों के रिकॉर्ड में बीमारों की संख्या का पता नहीं चल पाता है। ऐसी स्थिति कोरोना काल में भी हुई कई बीमारों का इलाज निजी तौर पर दाहोद, बड़ौदा, छोटा उदयपुर, इंदौर, बड़वानी आदि स्थानों पर किया गया, जिस कारण बीमारों की सही संख्या का पता नहीं रहा। ये ही स्थिति अब डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बीमारों की हो रही है। ऐसे बीमार शासकीय अस्पतालों की बजाय बाहर जाकर निजी चिकित्सालयों में इलाज करा रहे हैं। जिनकी जानकारी शासकीय रिकॉर्ड में नहीं है। क्षेत्र में अति शीघ्र दवा छिड़काव की मांग की जा रही है।

जिला चिकित्साधिकारी अलीराजपुर डॉ. प्रकाश ढोके से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि, आपने बताया तो पता चला मैं अति शीघ्र मलेरिया विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर उचित समाधान निकलता हूं।

जिला मलेरिया अधिकारी अलीराजपुर डॉ. जेएस कनेश ने बताया कि, मुझे आपसे तथा जिला चिकित्साधिकारी से जानकारी मिली है। अति शीघ्र टीम को आम्बुआ भेजकर जांच कराता हूं तथा यदि जरूरी हुआ तो दवा का छिड़काव कराऊंगा।

योजना सरकार की प्रचार पार्टी का...

माही की गूंज, झाबुआ।

जनकल्याण की कोई भी योजना हो, पार्टी से ऊपर उठकर सरकार की होती है, और सरकार का आशय ही पक्ष और विपक्ष दोनों से है, यानी सरकार बनने के बाद उसके लिए सभी बराबर होते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार की योजना पर पार्टी का प्रचार करने की परंपरा कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। जबकि सरकार की योजना पर आम नागरिक का अधिकार है, पार्टी के प्रचार का मंच नहीं। 2018 में भी कांग्रेस सरकार बनने के बाद थांदला क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक ने 26 जनवरी को ध्वजारोहण के लिए सभी सरकारी संस्थाओं में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए थे। भारी विरोध हुआ, और सुर्खियां प्रदेश स्तर तक पहुंची थी। मामले में विधायक साहब को स्पष्टीकरण तक देना पड़ा था।

कुछ ऐसा ही मामला गत दिनों उज्जवला योजना 2.0 के शुभारंभ पर देखने को मिला कि, जिसमें सरकारी योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर ने जिले के सभी गैस एजेंसियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए। वही प्रभारी मंत्री ने भी बकायदा.अपने हस्तांतरित लेटर पर जिले की सभी गैस एजेंसियों के लिए भाजपा नेताओं की सूची अतिथियों के रूप में आमंत्रित करने हेतु जारी की गई, और सभी जगह पर नोडल अधिकारी के साथ ही भाजपा नेताओं के आतिथ्य में उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया।

उज्जवला योजना मुख्यतः सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। जिसमें गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर और चूल्हा देना है। बेहतर यही होता कि, इस आयोजन में विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाता, और इसे सरकारी कार्यक्रम बनाया जाता जिसमें पक्ष-विपक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता, और इसे पार्टी की नहीं सरकार की उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जाता। यही नहीं यह योजना मुख्यतः महिलाओं के लिए थी। बेहतर यही होता कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल किया जाता। लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। अगर सबकुछ जनता का है तो जनता का जनता को देने में इतना प्रचार-प्रसार क्यों...? सरकारी योजनाओं के क्रियांनवयन में पार्टी का प्रचार प्रसार क्यों...?

स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी आवश्यक...

लोकतंत्र का मूल मंत्र ही पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर बना है, बिना विपक्ष के लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, हमारे संविधान निर्माताओं ने विपक्ष को सरकार के विरोध की महती जिम्मेदारी दी है, लेकिन प्रदेश सहित समूचे देश में इन दिनों विपक्ष के सुस्त रवैये के कारण सरकार को किसी प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बेहतर यही होता कि विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन करें, और सरकार के हर कार्यों पर पैनी नजर रखकर जन विरोधी कार्यों का पूरजोर विरोध करें।

प्रभारी मंत्री ने अपने भाजपा नेताओ को उज्जवला योजना मे गेस टंकी वितरण हेतु नियुक्त किए थे अतिथि।

जिला प्रशासन ने किए थे नोडल अधिकारी नियुक्त ।

मंडियों में नहीं मिल रहा किसानों को सब्जियों का भाव, दाम से ज्यादा मंडी तक सब्जी पहुँचाने का हो रहा खर्च

सब्जी उखाड़ कर फेंकने पर मजबूर हुए किसान, फसल आधारित उद्योग की दरकार

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गहलोत

बाज़ार में मिलने वाली हरी-भरी और ताज़ा सब्जी आपकी थाली तक भले ही महँगी पहुंचे, लेकिन उसको उपजाने वाले किसान को मिलने वाली उसकी मेहनत की कीमत तक वसुल नही हो रही है। देश मे कृषि कानून को लेकर जंग छिड़ी हुई है, हर कोई कृषि कानून को लेकर बड़े बड़े-बंगलो में बैठकर बयानबाज़ी करने में व्यस्त है, लेकिन वास्तविक किसान की स्थिति से हर कोई अनभिज्ञ है।

पेटलावद विकास खण्ड में पानी की उपलब्धता ने किसानों को मौसमी खेती से उभर कर खेती के नए मौके दिए जिसको देखकर क्षेत्र का किसान अपनी परंपरागत खेती छोड़ कर फल, सब्जी और अन्य प्रकार की खेती में पैसा और समय लगा रहा है। लेकिन कई किसानों के लिए यह कड़वा अनुभव साबित ही रहा है।

नहीं मिल रहे सब्जियों के सही दाम, फेंकने को हुए मजबूर

पेटलावद के बावड़ी क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में सब्जियों की खेती इस उम्मीद से करते है कि, अच्छा मुनाफा कमाएं और समय-समय पर पैसा मिलता रहे। परम्परागत फसलों की उपज लेने से अधिक सब्जिया उगाने में किसानों को खर्च करना पड़ता है, लेकिन सही दाम नही मिलने के कारण निराश होने के साथ-साथ नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राम बावड़ी के किसान जिन्होंने टमाटर, भिंडी, मिर्ची, ककडी आदि की खेती की थी, उनको वर्तमान में मिल रहे भाव से इतनी नुकसानी हो रही है कि, उन्होंने खेत से सब्जी उखाड़ कर फेकना मुनासिब समझा।

किसान सूर्यपाल सिंह राठौर, कान्हा चौधरी, पन्नालाल पाटीदार, जितेंद पाटीदार आदि ने बताया कि, आज की स्थिति में हालत इतने खराब है कि खेत मे लगी सब्जियां तोड़कर मंडी तक ले जाना भी महंगा पड़ रहा है। अभी मंडी में टमाटर 5 से 6 रुपए, मिर्ची व भिंडी 5 रुपए प्रति किलो है। लेकिन टमाटर तोड़ने के लिए मजदूरों को डेढ़ से दो रुपए प्रति किलो, मिर्ची तोड़ने के लिए 3 से 4 रुपए प्रति किलो मजदूरों को देना पड़ता है। ऊपर से मंडी तक ले जाने का खर्चा, मंडी टेक्स, दलाली ने सब्जी किसानों की कमर तोड़ दी है। इसलिए खेत मे लगी सब्जिया और उनके पौधे उखाड़ कर फेंक दिए।

भारतीय किसान यूनियन जिला महामंत्री जितेंद्र पाटीदार का कहना है कि, सरकार का किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। किसानों के लाभ की हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन पिछले डेढ़ महीने से किसानों की टमाटर, मिर्च और सब्जियां कोड़ी के दाम बिक रही है। पहले ही सरकार किसानों से फसल बीमा के नाम पर धोखा दे चूंकि है और अभी भी किसानों के खेत में फसले सुखने के कारण खाली होते जा रहे हैं। वही किसान बीमा तो हमारा होगा यह सोचकर बैठे थे, इतने में किसानों को पता चला कि मौसम आधारित बीमा टमाटर, मिर्ची व हाइब्रिड फसलों का बीमा बंद कर दिया गया है।

फसल आधारित उद्योगों की आवश्यकता

क्षेत्र में मिर्चि टमाटर के साथ-साथ सोयाबीन और कपास की बम्पर खेती होती है लेकिन इनसे जुड़े बड़े व्यापार की फैक्ट्रियां इस क्षेत्र में नही है जिस कारण किसानों को अपनी फसल बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। सरकार ने कसारबड़ी और बामनिया में उद्योग को बढ़ाने के उद्देश्य से हजारो स्केवयर फीट भूमि उद्योग विभाग को आबंटित की है लेकिन वर्षो के बाद एक भी सरकार की उद्योग नीति के कारण एक भी उद्योग यहां नही लग सका है । जबकि इस क्षेत्र के किसानों के भले के लिए टमाटर कैचप , कपड़ा मील, जिनिंग फेक्ट्री , सोया रिफायनरी जैसी फैक्ट्रियां या लघु उद्योग लगाए जा सकते है, जिससे किसानों की उपज सीधी इन उद्योगो को बेच कर अच्छा मुनाफा कमा सके। साथ ही क्षेत्र के नेता दिल्ली, भोपाल में किसानों और बेरोजगारी के लिए बड़े-बड़े दावे करते है लेकिन किसान और बेरोजगारों के लिए अवसर बने इसके कोई प्रयास धरातल करते नजर नही आते।

विधायक वालसिंह मैडा ने इस संबंध में कहा कि, मेरे द्वारा कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए कृषि कॉलेज की मांग की है जिसके लिए विधानसभा क्षेत्र में भूमि का सर्वे भी हो चुका है, साथ ही कसारबड़ी में बन्द पड़ी शक्कर मिल चालू करने के लिए उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तिगाव से मांग रखी है, टमाटर, मिर्ची का बड़ा रकबा होने से कैचप की फैक्ट्री लगाने की मांग की है ताकि यहाँ के टमाटर दिल्ली और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में नही ले जाना पड़े और यही अच्छी कीमत में बिक कर , पैकिंग होकर देश के हर कोने ओर विदेशों में पहुँचे। 15 महीने की सरकार मे क्षेत्र की इन मांगों को पूरा क्यो नही किया गया..? इस पर विधायक का कहना है कि, 15 महीने में से चार महीने तो लोकसभा चुनाव ओर झाबुआ उप चुनाव की आचार सहिता में निकल गए, 11 महीने में हमारे पूरे प्रयास थे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की उद्योग नीति अच्छी थी, अगर वो पूरे 5 साल सरकार चलाते तो क्षेत्र में उद्योग के लिए रास्ते खुलते जिसके लिए उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वस्त किया था। लेकिन भाजपा ने क्षेत्र के विकास को जनता द्वारा चुनी सरकार को गिरा कर ग्रहण लगा दिया।

इस संबंध में सांसद डामोर से भी चर्चा करने की कोशिश की गई लेकिन उनके दोनों नम्बर पर फोन अटेंड नही हुआ ।

प्राइवेसी की खामियां छिपा रहा व्हाट्सएप, रेडियो-टीवी और अखबार में विज्ञापनों का क्या मतलब?

नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने एक नई पॉलिसी लागू की है जिसके मुताबिक वह व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट से होने वाले चैट को पढ़ेगा और उसके हिसाब से यूजर को विज्ञापन दिखाएगा। व्हाट्सएप इस डाटा को फेसबुक के साथ भी साझा करेगा। प्राइवेसी विवाद के बाद से ही व्हाट्सएप विज्ञापन पर खूब पैसे खर्च कर रहा है। रेडियो से लेकर टीवी और अखबार के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब भी व्हाट्सएप के विज्ञापन से भरे पड़े हैं। समस्या विज्ञापन से नही समस्या उस प्राइवेसी को लेकर है जिसे लेकर व्हाट्सएप विज्ञापन पर इतने पैसे खर्च कर रहा है और निजता को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रहा है।

क्या वाकई एंड टू एंड एंक्रिप्टेड हैं व्हाट्सएप के मैसेज?

व्हाट्सएप हमेशा से यह दावा करता आ रहा है कि उसका एप पूरी तरह से एंड टू एंड एंक्रिप्टेड है, लेकिन साथ ही वह यह भी कहता है कि यदि आप किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जैसे गूगल ड्राइव पर चैट का बैकअप लेते हैं तो वहां एंक्रिप्शन खत्म हो जाता है। इसका प्रमाण दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह के मामले में देखने को मिला जब 2017 तक के व्हाट्सएप चैट पुलिस के हाथ लगे, हालांकि अब कंपनी के दावे के मुताबिक चैट का थर्ड पार्टी बैकअप भी एंड टू एंड एंक्रिप्टेड है। एंड टू एंड एंक्रिप्शन का मतलब यह है कि आप जिसके पास मैसेज भेजते हैं, उस मैसेज के बारे में आपको और सिर्फ उसे ही जानकारी होती है जिसके पास मैसेज जाता है। व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि यदि आपके मैसेज के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है तो कंपनी आपके मैसेज को डिक्रिप्ट करके पढ़ सकती है।

व्हाट्सएप कहता है कि वह आपके मैसेज को नहीं पढ़ता है लेकिन हाल ही में इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि, व्हाट्सएप ने करीब 1 हजार कंटेंट रिव्यूअर को नौकरी पर रखा है जो व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे कंटेंट (फोटो, वीडियो, मैसेज आदि) को देखते हैं। ये लोग ऑस्टिन, टेक्सास, डबलिन और सिंगापुर के ऑफिस से अपना काम करते हैं।

कलयुगी शिक्षक कुन्दन निकला कोयले की खान, अपनी ही शिष्या के साथ की छेड़-खानी

सोश्यल मिडिया पर कहा आई लव यू

मामला : स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इन्दरसिह परमार के गृह जिले का...

कलयुगी शिक्षक कुन्दन ने सोशल मिडिया पर छात्रा से कहा आई लव यू और छात्रा पर आई लव यू कहने का बनाया दबाव।

माही की गूंज, शाजापुर। अजयराज केवट

जहा 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के रूप मे मनाया जाता है वही शिक्षक को माता-पिता से भी उच्च दर्जा दे कर गुरू की पदवी दि गई है वही शिक्षक दिवस के इस पखवाडे मे ही नाम तो पिता गोविन्द ने अपने बेटे का कुन्दन रखा, पर यह कुन्दन पुत्र उर्फशिक्षक एक कलयुगी शिक्षक होकर अपनी ही शिष्या को पहले सोशल मिडिया पर वार्तालाप कर बदनियत से आई लव यू कह डाला और फिर छात्रा से आई लव यू कहने के लिए भी सोशल मिडिया पर दबाव बनाता रहा लेकिन छात्रा ने अपनी मान-मर्यादा एवं परिवार की प्रतिष्ठा के साथ अपने संस्कारो को महत्व देकर कलयुगी शिक्षक के झासे मे नही आई, तो स्कुल मे जब छात्रा आई तो कलयुगी शिक्षक ने छात्रा के साथ छेडखानी की हरकत करने मे भी नही चुका। यह पुरा मामला कही और का नही बल्कि स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार के गृह जिले शाजापुर का है।

कलयुगी शिक्षक कुन्दन

शासकीय उत्कृष्ट स्कूल के शिक्षक द्वारा अपनी बेटी की उम्र की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छात्रा के स्वजन ने स्कूल पहुंचकर शिक्षक को सबक सिखाते हुए सार्वजनिक रूप से स्कूल में स्वजन द्वारा शिक्षक की पिटाई भी की गई। स्कूल स्टाफने बमुश्किल शिक्षक को नाराज लोगों से बचाया। स्कूल के जिम्मेदारों का कहना था कि, शिक्षक की करतूत के बारे में उन्हें कोई जानकारी नही है। ग्राम मोरटा केवड़ी निवासी कक्षा 12वीं की एक छात्रा ने स्कूल के शिक्षक कुंदन पिता गोविंद प्रसाद वर्मा (52) के खिलाफशिकायत दर्ज कराई गई है। छात्रा द्वारा की गई शिकायत के अनुसार शिक्षक वर्मा द्वारा सोमवार को उसे अलग कमरे में बुलाया और गलत नीयत से हाथ पकड़ लिया। शिक्षक दस दिनों से बात करने के लिए परेशान कर रहा है। शिक्षक द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से भी छात्रा को अश्लील संदेश भेजे गए जिसमे कलयुगी शिक्षक ने छात्रा को प्रपोज करते हुए आई लव यु तक कह दिया, जिसके स्क्रीन शाट भी पुलिस को दिए गए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहै है। छात्रा ने बताया कि, शिक्षक ने उसे अकेले में मिलने बुलाया। नहीं आने पर फेल करने की धमकी दी। इस पर छात्रा ने शिक्षक की हरकतों के बारे में अपने परिजनो को बताया। नाराज परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षक की पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस को शिकायत की गई।

मोर में नाच रहा चोर...!

झालावाड़ में हुई चार लाख की चोरी में राजस्थान पुलिस को मोर के कृष्णपाल सिंह की तलाश...

पकड़े गए आरोपियों ने उगला कृष्णपाल का नाम और भी बड़ी वारदातों से जुड़े हो सकते है तार

माही की गूंज, पेटलावद।

ऐश, अय्यासी और मंहगे शोक ने युवाओं को अपराधों की तरफधकेल दिया है। सामान्य से दिखने वाले कई युवा जो अपनी कमाई से ज्यादा पैसा उड़ाते देखे जा सकते है ऐसे में इन सब के पीछे किसी बड़े अपराध या फिर किसी बड़े गिरोह के साथ होने की संभावनाएं होती है, लेकिन परिवार और समाज इन पर लगाम नही कस पाते है।

ऐसा ही मामला सामने आया जहा पेटलावद थाना क्षेत्र की करवड़ चौकी में पड़ने वाले मोर गांव के युवक कृष्णपाल सिंह की तलाश झालावाड़ (राज.) की पुलिस 4 लाख की चौरी के मामले में कर रही है। बताया जा रहा है, राजस्थान की पुलिस मोर निवासी कृष्णपाल की तलाश में पहुची थी लेकिन वो फिलहाल पुलिस के हत्थे नही चढ़ा है।

व्यापारी के यहां चार लाख की नकबजनी का खुलासा, घटना में शामिल सभी अभियुक्तो में एक पेटलावद थाना क्षेत्र का

जिला झालावाड़ (राज.) एसपी डॉ. किरण कंग सिद्धू ने बताया, 18 अगस्त की शाम चौमहला में व्यापारी हंसराज जैन की किराने की दुकान में घुसकर दो नकाबपोशों द्वारा गल्ले में से करीब चार लाख रूपए की नकबजनी की वारदात का थाना गंगधार द्वारा खुलासा करते हुए वारदात करने वाले लोकेन्द्र सिंह व मांगीलाल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। प्रकरण में एक मुलजिम कृष्णपाल सिंह निवासी मोर थाना पेटलवाद जिला झाबुआ मध्य प्रदेश फरार है, जिसकी टीम द्वारा तलाश की जा रही है।

फरीयादी आदित्य जैन पुत्र हंसराज जाति महाजन निवासी चोमहला थाना गंगधार ने एक लिखित रिपोर्ट में बताया कि, मेरी दुकान मेन बाजार में है। 18 अगस्त करीब साढ़े 9 बजे दुकान का शटर लगाकर हम सब परिवार वाले उपर मकान पर चले गए। हमारे पीछे से दो अज्ञात आदमी दुकान का सटर उंचा करके अन्दर दुकान में प्रवेश करके गल्ले में रखें दिनभर की बिक्री के रुपए करीब चार लाख रुपए निकाल कर ले गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।

आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु गठीत टीम द्वारा कस्बा चोमहला में विभिन्न स्थानों पर लगे करीब तीस सीसीटीवी कैमरों को घटना के समय को ध्यान में रखते हुए देखा गया, तथा सीसीटीवी फुटैज के हुलिए वाले 22 संदिग्धो की पहचान कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दोरान अभियुक्त लोकेन्द्र सिंह पिता विक्रमसिंह (33) निवासी निपानिया झाला थाना गंगधार, मांगीलाल पिता राधेश्याम जाति ब्रहाम्ण (26) निवासी पारापीपली थाना गंगधार, कृष्णपाल सिंह पिता दशरथ सिंह जाति पंवार राजपुत निवासी मोर थाना पेटलावद जिला झाबुआ मध्यप्रदेश का वारदात में संलिप्त होना पाया गया, जिनकी घटित टीम द्वारा घर पर तलाश की तो घर से भी फरार मिले। राजस्थान की पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर वारदात के दो आरोपियों को रतलाम मध्य प्रदेश से पकड़ने में सफलता प्राप्त की तथा एक आरोपी की तलाश जारी है।

अय्याशी के लिए कर रहे थे चोरी

पुछताछ पर आरोपियों ने बताया कि, मोबाईल, कपडे, जुते व अन्य प्रकार से स्टैण्डर्ड लाईफ स्टाइल मेन्टेन करने के लिए चोरी कर रहे थे, ताकि यार-दोस्तों में अपना रुबाब जमा सके। इन सब ने मिलकर कितनी वारदातों को अंजाम दिया है इसकी जांच की जा रही है।

हो सकता है और वारदातों का खुलासा, गुजरात मे भी दे चुका है वारदात को अंजाम

सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार आरोपी कृष्णपाल सिंह पंवार की आपराधिक मानसिकता पहले से है और लगभग डेढ़-दो वर्ष पूर्व गुजरात के अंकलेश्वर में किसी कम्पनी में भी वारदात को अंजाम दे चुका है। बताया जा रहा है, तब भी कृष्णपाल पुलिस के हत्थे नही चढा था। जानकारी ये भी मिली है कि, कृष्णपाल सिंह अपने गांव में बहुत कम रहता है और ज्यादातर बाहर ही रहता है, लेकिन कुछ समय पूर्व यही रह रहा था। पूरे मामले में राजस्थान, गुजरात और मध्यप्रदेश राज्य से जुड़ता नजर आ रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद किसी अंतरराजिय गिरोह का भंडाफेड़ हो सकता है और कई बड़ी वारदातो का खुलासा हो सकता है।

भाजपा से जुड़ा परिवार

झालावाड़ चोरी का आरोपी कृष्णपाल सिंह पंवार का परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है बताया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि, आरोपी के पिता दशरथ पंवार मोर क्षेत्र में भाजपा के मुख्य कार्यकर्ता है ओर चुनाव में भाजपा का सेक्टर प्रभारी रह चुका है। मोर पंचायत सहित आस-पास की 4 से 5 पंचायतो का प्रभार इनके पास रहता है। हालांकि ग्रामीण मंडल अध्यक्ष सुखराम मोरी से इस विषय मे जानकारी ली तो उन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नही होने की बात कही है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा, संपादक- धर्मेन्द्र पंचाल । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422